

सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच



वर्ष- 18 अंक - 44 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 27 नवम्बर 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास - खबर



क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड का स्कोर 246/5

क्राइस्टचर्च। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के पहले दिन 5 विकेट पर 246 रन बनाए। स्टंप्स पर टॉम ब्लंडेल 53 और ग्लेन फिलिप्स 36 रन बनाकर नाबाद रहे। शुक्रवार को भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हालांकि, भारतीय गेंदबाज हेगले ओवल स्टेडियम की बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस का फायदा नहीं उठा सके। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 77/1 था। गुरनूर बरार ने डेवोन कॉन्वे का विकेट लेकर ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक की। दूसरे सेशन में भारत ने लगातार 3 ओवर में 3 विकेट लेकर वापसी की। यहां पर रचिन रवींद्र जीरो, हेनरी निकल्स 16, कप्तान टॉम लैथम 59 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आखिरी सेशन में कीवियों ने 115 रन बनाकर बढ़त ली। यहां डेरिल मिचेल 31 रन बनाकर आउट हुए।

वडोदरा से जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, एके 47 बरामद

वडोदरा। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गुजरात एटीएस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में वडोदरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी ने एजेंसियों को अहम सुराग दिए हैं और यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकियों की सक्रियता को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) को वडोदरा में एक बस स्टैंड के पास से जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी को दबोचने में कामयाबी मिली है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी के असम से गुजरात पहुंचने की बात मानी जा रही है और उसके पास से एक ८-47 राइफल व लगभग 23 कारतूस मिले हैं। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाया गया था, इसे किसे सौंपा जाना था और आरोपी जैश के किन लोगों के संपर्क में था।

पाकिस्तान बॉर्डर पर पांचवां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा भारत

नई दिल्ली। भारत जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान से लगे 740 किलोमीटर लंबे नियंत्रण रेखा (LoC) पर सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पांचवां एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की योजना है। इससे पहले चार को सीमा पर अलग-अलग जगह तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से इनके लोकेशन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वायुसेना की एक टीम अगले महीने रूस जाकर इस सिस्टम का प्री-डिस्पैच इंस्पेक्शन करेगी। इसके फरवरी 2027 तक तैनाती के लिए तैयार होने की उम्मीद है। यह जानकारी मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने दी है।

नगरीय निकाय चुनाव 2027 : दिसंबर के पहले सप्ताह में लगेगी आचार संहिता, 25 दिनों में पूरी होगी चुनावी प्रक्रिया

नगर निगम भिलाई सहित चार निगमों में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में, 30 नंवबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

हर्षित अग्रवाल

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के चार नगर निगमों व अन्य निकायों में चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए प्रतिष्ठित इन चुनावों के तारीखों की घोषणा दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। पिछली बार की ही तरह इस बार भी चुनाव काफी तेजी से संपन्न कराए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचय आयोग द्वारा महज 25 दिनों के भीतर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही कांउट डाउन शुरू हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव के साथ रिजल्ट की घोषणा भी हो जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 या 3 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयुक्त



चुनाव की तारीखों के ऐलान और आचार संहिता लागू करने के निर्देश जारी कर सकते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान कराया जा सकता है। इससे पहले 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इसके बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है। इसके अंतर्गत दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई, भिलाई-चरोदा, रिसाली व रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम समेत अन्य नगरीय निकायों में मतदान होगा।

पिछली बार 23 दिन में पूरी हुई थी चुनावी प्रक्रिया

2021 में नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ था। इसके बाद 20 दिसंबर को मतदान कराया गया था। यानी चुनाव की अधिसूचना जारी होने से मतदान तक करीब 23 दिन का समय मिला था। इसी समय-सीमा को देखते हुए इस बार भी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ही होगा। यदि चुनाव कार्यक्रम जारी करने में देरी होने पर कुछ नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने पड़ सकते हैं। ऐसे में दिसंबर का पहला सप्ताह राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से अहम रहेगा। पिछले चुनाव से पहले भी प्रशासक नियुक्त किए गए थे।

दुर्ग जिले के तीन नगर निगमों में होंगे चुनाव, बनेंगे 744 मतदान केंद्र

नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत दुर्ग जिलें में सर्वाधिक तीन नगर निगमों में चुनाव होंगे। नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम भिलाई-चरोदा और नगर पालिक निगम रिसाली में महापौर व पार्षदों के चुनाव होंगे। इसके साथ ही नगर पालिकाओं, त्रिस्तरीय उप चुनाव भी होने हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि जिले के तीन नगर निगम एवं एक नगर पालिका में आम चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 30 नवंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए जिले में कुल 744 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। सभी नगरीय निकायों में नोडल एवं सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इन अधिकारियों का प्रशिक्षण आगामी दो से तीन दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चारों नगरीय निकायों के लिए मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम के कक्षों का निर्धारण कर लिया गया है। इन स्थानों पर आवश्यक सिविल कार्य आगामी तीन से चार दिनों में पूर्ण कर लिए जाएंगे।

पूरे प्रदेश में कुल 1231 पदों के लिए होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, नगरीय निकायों में आम निर्वाचन, त्रिस्तरीय पंचायतों, उपचुनाव को मिलाकर कुल 1231 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें चार नगर निगमों में महापौर के 4, अध्यक्ष के 13 और पार्षद के 400 पद शामिल हैं। इसके अलावा उपचुनाव में अध्यक्ष के एक और पार्षद के 6 पदों पर चुनाव होगा। वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 814 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें जनपद पंचायत सदस्य का एक, सरपंच के 92 और पंच के 721 पद शामिल हैं।

महादेव सट्टा केसः दिल्ली में कैटरर राहुल मक्कर और कारोबारी ग्रोवर परिवार के ठिकानों पर छापे

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए दिल्ली में कई कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान लग्जरी कैटरिंग व्यवसायी राहुल मक्कर और रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर तथा उनके बेटे माधव ग्रोवर से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी को आशंका है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित करोड़ों रुपये इन कारोबारी नेटवर्क तक पहुंचाए गए और बाद में उन्हें दुबई के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तथा भारत के हॉस्पिटैलिटी कारोबार में लगाया गया।

ईडी की जांच अब केवल सट्टा संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि कथित अवैध कमाई के लेन-देन, निवेश और उससे जुड़े कारोबारी संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, ग्रोवर पिता-पुत्र से जुड़ी नौ कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। गुरुवार को हुई कार्रवाई में श्रेष्ठ की टीमों ने दिल्ली के पॉश जोरबाग इलाके में शेली ग्रोवर से



जुड़े दो आवासीय परिसरों की तलाशी ली। इसके अलावा खान मार्केट स्थित उनके व्यावसायिक कार्यालय में भी जांच की गई। राहुल मक्कर से जुड़े रिवेरा हाउस और उनके स्वामित्व वाले कई वेडिंग वेन्यू पर भी छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान मिले वित्तीय दस्तावेजों, कंपनियों के रिकॉर्ड और संपत्तियों से संबंधित कागजात की जांच की जा रही है। एजेंसी इन दस्तावेजों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित सट्टे की रकम किन कंपनियों और व्यक्तियों के माध्यम से आगे भेजी गई।

परिसीमन विधेयक पर एनडीए का साथ देगी जगन की पार्टी

नईदिल्ली। अठारहवीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा भाग 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत दोनों सदनों की संक्षिप्त बैठकें बुलाई गई हैं। कम समय के नोटिस पर बुलाई गई इन बैठकों से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विधेयकों को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच वाईएसआरसीपी के संभावित समर्थन ने सियासी समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है। वाईएसआर कांग्रेस संसद में परिसीमन विधेयक लाए जाने पर पार्टी उसका समर्थन करने को तैयार है। हालांकि, पार्टी ने इसके साथ क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित किए जाने की शर्त रखी है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश में लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना बताया जा रहा है।

मौसम साफ होने के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ी ठिठुरन, 13 जिलों में 15 डिग्री से कम

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। छत्तीसगढ़ में बादल छंटने और मौसम साफ होने के बाद ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 15 डिग्री से कम है। सबसे ज्यादा असर सरगुजा संभाग के जिलों में दिखाई दे रहा है। यहां बलरामपुर-रामानुजगंज में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सूरजपुर में 9.4 और सरगुजा में 9.2 डिग्री रहा। सूरजपुर में तापमान सामान्य से 7.1 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं बालोद में भी पारा सामान्य से 6.6 डिग्री और बेमेतरा में 6.5 डिग्री कम रहा।

मौसम विभाग के अनुसार मौसम साफ होने के कारण रात में ठंड का असर बढ़ा है, जबकि दिन में धूप निकलने से अधिकतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं है। प्रदेश में मौसम फिलहाल ड्राई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, लेकिन इसका छत्तीसगढ़ पर खास असर नहीं है। कोई अलर्ट नहीं है।

बस्तर में रात का पारा 21 डिग्री

छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में जहां रात का पारा 8.8 डिग्री तक पहुंच गया है, वहीं बस्तर संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच बना हुआ है। बलरामपुर-रामानुजगंज में सबसे कम 8.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जबकि सुकमा में 21 डिग्री रहा। यानी दोनों जिलों के तापमान में 12.2 डिग्री का अंतर है।

सक्ति में 400 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू

सक्ति। जिले में शासकीय और निजी जमीन को कथित तौर पर फर्जी तरीके से निजी नामों पर दर्ज कराने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता रमेश चंद्रा ने जैजैपुर ब्लॉक के झालरौंदा गांव में तत्कालीन पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार पर करीब 400 एकड़ जमीन के रिकॉर्ड में कथित फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू की गई है।

शिकायत के मुताबिक, जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर के आधार पर धान बोनस और बैंक लोन भी लिया गया। शिकायतकर्ता रमेश चंद्रा ने प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि जैजैपुर ब्लॉक के झालरौंदा गांव में तत्कालीन पटवारी विशेश्वर सिंह सिदार ने करीब 400 एकड़ शासकीय और निजी जमीन को अलग-अलग लोगों के नाम पर कथित तौर पर फर्जी तरीके से दर्ज कराया है। इस जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर पिछले साल करोड़ों रुपये का धान बोनस और बैंक लोन भी लिया गया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

महासमुंदः कार में मिली 90 लाख की चांदी, तीन लाख नगद भी बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में चांदी के अवैध परिवहन के मामले में महासमुंद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 52 किलो चांदी बरामद की है। वाहन जांच के दौरान बसना पुलिस ने पलसापाली चेकपोस्ट पर गुरुवार को तकरीबन 90 लाख रुपए से ज्यादा की चांदी को जब्त करते हुए इसकी जानकारी जीएसटी विभाग को भी भेजी है।

जानकारी के अनुसार वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मारुति सुजुकी विक्टोरियस कार क्रमांक सीजी 23 क्यू 9222 से



भारी मात्रा में चांदी के आभूषण, बर्तन, मूर्तियां, छह चांदी जैसी सिल्लियां और नकदी बरामद की। बरामद चांदी का कुल वजन 52 किलो 528 ग्राम (रैपर सहित) बताया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 90 लाख रुपए है।सोना खरीदें

अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर पुलिस की सख्त निगरानी

पुलिस के अनुसार, जिला पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तस्करी, संदिग्ध नकदी तथा बहुमूल्य धातुओं के अवैध परिवहन की मिली जानकारी के आधार पर गुरुवार को थाना बसना पुलिस की टीम पलसापाली अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की मारुति सुजुकी विक्टोरियस कार को रोककर तलाशी ली गई। कार में उमेश कंसारी, उम्र 45 वर्ष, निवासी गोबरानवापारा जिला रायपुर तथा रोशन कुमार साहू, उम्र 40. वर्ष, निवासी बेलटूकरी थाना राजिम जिला गरियाबंद सवार थे।

बर्तन, मूर्तियां और सिल्लियों के रूप में मिली चांदी

तलाशी के दौरान कार की डिक्की और सीट में रखे छह काले रंग के बैग पुलिस को मिले। बैगों की जांच करने पर प्लास्टिक के डिब्बों में अलग-अलग प्रकार के चांदी जैसे आभूषण, बर्तन, मूर्तियां और सिल्लियां रखी मिलीं। इनमें पायल, बिछिया, अंगूठी, चैन, कड़ा, बेसलेट, करधन सहित अन्य आभूषण शामिल थे। इसके अलावा नकदी रकम भी बरामद हुई। दोनों व्यक्तियों से बरामद सामग्री के वैध स्वामित्व तथा उसके क्रय-विक्रय से संबंधित जीएसटी बिल, ई-वे बिल और परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। पुलिस के अनुसार दोनों व्यक्ति मौके पर इन सामग्रियों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

व्हाट्सएप में बड़ी सुरक्षा चूकः एक मैसेज से हैक हो सकता है आपका फोन, सीईआरटी-इन ने जारी किया हाई अलर्ट

नईदिल्ली। व्हाट्सएप पर आने वाला एक मैसेज आपकी निजी जानकारी के लिए खतरा बन सकता है। भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने मैसेजिंग एप में कई गंभीर सुरक्षा खामियों को लेकर हाई-सीवियरिटी अलर्ट जारी किया है। एजेंसी के मुताबिक इन कमियों का फायदा उठाकर हैकर्स फोन में मौजूद जानकारी तक पहुंच सकते हैं। कुछ मामलों में व्हाट्सएप का डेटा डिलीट होने का खतरा भी है। ऐसे में यूजर्स को तुरंत एप अपडेट करने की सलाह दी गई है।

CERT-In ने 26 नवंबर को जारी अपनी एडवाइजरी में व्हाट्सएप के अलग-अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ी पांच कमजोरियों का जिक्र किया है। ये खामियां एंड्रॉइड, आईओएस, मैक और



विंडो यूजर्स को प्रभावित कर सकती हैं। हैकर्स खास तरीके से तैयार किए गए मैसेज, अटैचमेंट या लिंक भेजकर इनका फायदा उठा सकते हैं। एजेंसी ने आम लोगों के साथ कंपनियों और दूसरे संस्थानों को भी व्हाट्सएप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने की सलाह दी है। इन खामियों की गंभीरता को देखते हुए यूजर्स को अनजान मैसेज और फाइल खोलने में सावधानी बरतने की जरूरत है।

एक मैसेज से डिलीट हो सकता है व्हाट्सएप डेटा

सीईआरटी-इन की एडवाइजरी में बताई गई पहली खामी CVE-2026-102769 है। इसमें खास तरीके से तैयार किया गया 'ऑर्डर डिटेल्स' मैसेज एंड्रॉइड यूजर्स के लिए खतरा बन सकता है। अगर यूजर इस मैसेज पर टैप करता है, तो स्क्रिप्ट इंजेक्शन की मदद से फोन में स्थानीय रूप से सेव व्हाट्सएप फाइलें डिलीट हो सकती हैं। इसके अलावा, मैसेज डिलीवर होने के समय और क्रैश की स्थिति से हैकर चैट डेटाबेस से जुड़ी सीमित जानकारी का अंदाजा लगा सकता है। हालांकि व्हाट्सएप ने कहा है कि उसे इस खामी के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला है।

संपादकीय

अपने घर में डर

सुनिश्चित हो महिलाओं की सुरक्षा-भरोसा

यह एक वैश्विक आंकड़ा है कि दुनिया में हर एक घंटे में पांच महिलाओं या लड़कियों की हत्या उनके जीवन साथी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा कर दी जाती है। वर्ष 2025 की यूएन वूमेन-यूएनओडीसी रिपोर्ट का यह चौंकाने वाला खुलासा, हमारा सामना एक कठोर यथार्थ से कराता है। यह सत्य कि दुनिया में लाखों महिलाओं की जान के लिये सबसे बड़ा खतरा अनजान लोगों से नहीं, बल्कि उन लोगों से है, जिनके साथ वे पारिवारिक संस्था के भीतर रहती हैं। जिन पर अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा करती हैं।

> **“ यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि बीते वर्ष दुनिया भर में इरादतन मारी गई करीब 78 हजार महिलाओं व लड़कियों में से 47 हजार की हत्या उनके पार्टनर या रिश्तेदारों ने की। यह दुखद ही है कि जो घर महिलाओं के लिये सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है, वही आज उसके लिये खतरनाक जगह बन रही है। हालांकि, भारत में ऐसी भयावह स्थिति नहीं है,लेकिन आंकड़े कुछ चिंताजनक संकेत जरूर दे रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार देश में 18 से 49 आयुवर्ग वाली 29 फीसदी विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की जाने वाली हिंसा का त्रास झेला।**

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि बीते वर्ष दुनिया भर में इरादतन मारी गई करीब 78 हजार महिलाओं व लड़कियों में से 47 हजार की हत्या उनके पार्टनर या रिश्तेदारों ने की। यह दुखद ही है कि जो घर महिलाओं के लिये सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान माना जाता है, वही आज उसके लिये खतरनाक जगह बन रही है। हालांकि, भारत में ऐसी भयावह स्थिति नहीं है,लेकिन आंकड़े कुछ चिंताजनक संकेत जरूर दे रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार देश में 18 से 49 आयुवर्ग वाली 29 फीसदी विवाहित महिलाओं ने अपने पति द्वारा की जाने वाली हिंसा का त्रास झेला। वहीं यूएन वुमेन के आंकड़े बताते हैं कि शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार महिलाओं में सिर्फ 14 फीसदी ने ही मदद की गुहार लगायी। उससे ज्यादा चिंताजनक यह कि इसमें सिर्फ 5.6 फीसदी महिलाओं ने ही मदद हेतु पुलिस से संपर्क किया। दरअसल, परंपरागत भारतीय घरों में महिलाओं की प्राथमिकता परिवार बचाना होती है। सामाजिक बदनामी, आर्थिक असुरक्षा, बदले की कार्रवाई का डर और शादी को टूटने से बचाने के भय के चलते महिलाएं चुप रहने को बाध्य हो जाती हैं। इसके बावजूद हिंसा की रिपोर्ट न करने के पीछे की हिचकिचाहट को हिंसा न होने का संकेत नहीं मान लिया जाना चाहिए।

इसमें दो राय नहीं है कि घरेलू हिंसा रोकने, पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता और दहेज से जुड़े दुर्व्यवहार पर लगाम के लिये देश में पर्याप्त कानून हैं। लेकिन जब तक इन कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता, तब तक ये कानून महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इस तरह के मामलों में मायके वालों से भी संवेदनशील और सतर्क व्यवहार अपेक्षित है। वास्तव में पुलिस को बार-बार मिलने वाली शिकायतों व धमकियों और दबाव डालने वाले व्यवहार को केवल सामान्य पारिवारिक झगड़े के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सही मायने में इसे गंभीर चेतावनी संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर को कायदे से लागू किया जाना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की संस्था के भीतर सुरक्षित महसूस न करने वाली महिलाओं के लिये वैकल्पिक आश्रय स्थल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिये सहजता से कानूनी मदद का प्रावधान होना आवश्यक है। किसी मानसिक आघात से उबरने के लिये काउंसलिंग और तात्कालिक आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिससे वे बिना किसी आर्थिक तंगी के या बेसहारा हुए, हिंसक रिश्तों से बाहर निकल सकें। यानी सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। वास्तव में प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसी महिला के जीवन का अंत न हो। वहीं परिवारों, समुदायों और संस्थाओं को हिंसा को सामान्य बात मानना बंद करना होगा। दूसरी ओर महिलाओं पर चुप रहने के लिये दबाव डालना भी बंद करना होगा। निस्संदेह, पुलिस, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सहायता प्रदान करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से किसी भी महिला के जीवन पर आसन्न संकट को जानलेवा बनने से पहले ही पहचाना जा सकता है। सही मायने में किसी भी महिला का सुरक्षा अधिकार इस बात का मोहताज नहीं होना चाहिए कि उसके पास किसी हिंसक घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है। या फिर अलग जीवन जीने के लिये आर्थिक संसाधन नहीं हैं। पुलिस व कानून-कचहरी से इतर मां-बाप को बेटियों को शारीरिक व मानसिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाना चाहिए कि वे घर के भीतर किसी भी अन्याय, शोषण और हिंसा का प्रतिकार कर सकें। यदि ऐसा साहस न जुटा पाएं तो कम से कम परिजनों को समय रहते अनुचित या हिंसक व्यवहार से अवगत करा सकें।

बाल विवाह मुक्त भारतः हर बेटी के सपनों को पूरा करने का संकल्प



सावित्री ठाकुर



विवाह जीवन के एक नए अध्याय का आरंभ होता है लेकिन जब दूल्हा या दुल्हन स्वयं बच्चे हों, तो यह उनके बचपन का अंत बन जाता है। जिस उम्र में बच्चों को अपनी पहचान बनानी चाहिए, सपने देखने चाहिए और शिक्षा के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहिए, उस उम्र में उन पर ऐसी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, जिनके लिए वे तैयार नहीं होते। बाल विवाह केवल पीढ़ियों से चली आ रही कोई सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का हनन और उनके बचपन के साथ अन्याय भी है। 14 साल की उम्र में जिस बेटी के हाथों में किताबें होनी चाहिए, उस उम्र में उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं।

पिछले दो दशकों में लगातार किए गए प्रयासों और मजबूत इच्छाशक्ति के कारण भारत में बाल विवाह के मामलों में काफी कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6, 2023-24) के आंकड़ों के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु की ऐसी महिलाओं की संख्या में कमी आई है, जिनका विवाह 18 वर्ष की उम्र से पहले हुआ था। अब यह आंकड़ा घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है। दो दशक पहले एनएफएचएस-3 (2005-06) में यह आंकड़ा 47.4 प्रतिशत था। यह 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट लाखों बेटियों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। आज 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि, हर पांच में से एक युवती का बाल विवाह होना अब भी एक बड़ी चुनौती है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देश ने एक स्पष्ट समय-सीमा तय की है - वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त भारत।

बाल विवाह मुक्त भारतः दो वर्षों की निर्णायक यात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखा गया है। इसी संकल्प को गति देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 5.3 के अनुरूप 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की शुरुआत की। पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित इस अभियान में देश के 257 उच्च-प्रभावित जिलों को प्राथमिकता दी गई है। यह अभियान केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाता है।

पिछले दो वर्षों में इस अभियान ने जमीनी स्तर पर व्यापक प्रभाव डाला है। अब तक 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 12.47 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाया जा चुका है और 42 लाख से अधिक नागरिकों ने बाल विवाह के विरुद्ध शपथ ली है। 'बाल विवाह मुक्त भारत' पोर्टल पर 71,900 से अधिक बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 60,000 ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 4,500 से अधिक मामलों की सूचना दर्ज की जा चुकी है।

नवंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच चलाए गए पहले 100-दिवसीय विशेष अभियान ने इस संदेश को स्कूलों और कॉलेजों से लेकर मंदिरों, मस्जिदों, कैटरर्स, टेंट हाउस, डीजे संचालकों और ग्राम पंचायतों तक पहुंचाया। इसके उत्साहजनक परिणाम धरातल पर दिखने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, जहां 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी स्थानीय निकायों में लगातार दो वर्षों तक एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी प्रकार सूरजपुर जिले ने अपनी 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है।

कठोर कानून और रोकथाम पर जोर

बाल विवाह के विरुद्ध भारत का संघर्ष राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों की विरासत से जुड़ा है, जिसकी परिणति बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के रूप में हुई। आज कानून पूरी तरह स्पष्ट है: 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह निषिद्ध है। ऐसा विवाह करवाने, बढ़ावा देने या इसमें शामिल होने वाले माता-पिता और अभिभावकों को दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है।

नए आपराधिक कानूनों ने इस दिशा में किसी भी संदेह की गुंजाइश समाप्त कर दी है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का यौन संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पॉक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत गंभीर अपराध माना है। इसके साथ ही, 18 अक्टूबर 2024 के अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने दंड के बजाय रोकथाम पर जोर देते हुए पूर्णकालिक सीएमपीओ की नियुक्ति और बाल सगाई पर प्रतिबंध के निर्देश दिए।

ग्राम सभा और समुदाय की अग्रणी भूमिका

कानून आवश्यक हैं, लेकिन केवल कानून से उस कुप्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता जिसे सामाजिक स्वीकृति और चुप्पी का सहारा मिला हो। बाल विवाह गांव और समाज के भीतर तय होते हैं, इसलिए इनका अंत भी वहीं होना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी करते हुए अब ग्राम सभाओं को इस मिशन की अगली पंक्ति में रखा गया है। 2 अक्टूबर को देश भर की ग्राम सभाओं से अपने गांवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया गया। स्थानीय सीएमपीओ द्वारा सत्यापन के बाद ही सरपंच, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास अधिकारी और सीएमपीओ के संयुक्त हस्ताक्षर से 'बाल विवाह मुक्त ग्राम प्रमाण-पत्र' जारी किया जाएगा।

इसके साथ ही, मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को भी 'बाल विवाह मुक्त भारत' से जोड़ा गया है। स्कूल में लौटने वाली हर बेटी बाल विवाह से सुरक्षित होती है। अब दोनों अभियानों का साझा मंत्र होना चाहिए - 'पहले पढ़ाई, फिर शादी'। जब कोई पुजारी या कैटरर नाबालिग के विवाह में सेवा देने से इनकार करता है और जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सरपंच सतर्क रहते हैं, तब बाल विवाह को सहारा देने वाली चुप्पी टूटती है।

27 नवंबर का महत्व और हमारा सामूहिक वादा

27 नवंबर 2026 का दिन विशेष महत्व रखता है। एक ओर यह 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के दो वर्ष पूर्ण होने का अवसर है, तो दूसरी ओर इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित पहला 'अंतर्राष्ट्रीय बाल, प्रारंभिक और जबरन विवाह उन्मूलन दिवस' मनाया जाएगा, जिसके प्रस्ताव का भारत सह-प्रायोजक रहा है। यह दिवस लैंगिक हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय अभियान (25 नवंबर से 10 दिसंबर) के मध्य आता है, जो इस सत्य को रेखांकित करता है कि बाल विवाह स्वयं एक हिंसा है और अक्सर घरेलू हिंसा का द्वार खोलता है। बाल विवाह कोई निजी पारिवारिक मामला नहीं है। मंत्रालय का राष्ट्रीय अभियान 'नंबर सेव किया?' हर परिवार को याद दिलाता है कि वे संकट में फंसे बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन 181 को अपने फोन में सुरक्षित रखें और किसी भी संभावित बाल विवाह की सूचना पोर्टल या मिशन शक्ति ऐप पर दें।

जो बेटी पढ़ाई पूरी कर अपने पैरों पर खड़ी होती है और अपने जीवन के निर्णय खुद लेती है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही बेटियाँ विकसित भारत के सपने को साकार करने में योगदान देंगी। हमारा संकल्प है कि 2030 तक भारत पूरी तरह बाल विवाह मुक्त हो। यह केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि हर बेटी के बेहतर भविष्य के लिए हमारा दायित्व है, जिसे हमें मिलकर पूरा करना है।

(लेखिका सावित्री ठाकुर, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं।)

नगीना बनने को पसीना बहाते हर्ष संघवी

अरूण नैथानी

हर्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आंखों का तारा बने हुए हैं। राज्य में सबसे कम उम्र में उपमुख्यमंत्री बनने वाले संघवी राज्य में भाजपा का भविष्य का चेहरा हैं। वे राज्य के छठे उपमुख्यमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक पारी लंबी होने वाली है। गुजरात को भाजपा की राजनीति की मुख्य प्रयोगशाला कहा जाता है। अक्सर यह भी दोहराया जाता रहा है कि देश में गुजरात मॉडल पर ही काम किया जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि देश को गुजरात की धरा में उपजी राजनीति ही संचालित कर रही है। ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि वर्तमान में राजग सरकार में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर इसी राज्य के सशक्त प्रतिनिधि विराजमान हैं। लेकिन यदि 2014 के बाद गुजरात के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात जरूर सामने आती है कि केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के बाद राज्य में कोई ऐसा नेता नहीं उभरा, जो लंबी पारी खेलने वाले पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जैसी स्वतंत्र पहचान बना सका हो। यूं भी देश का नेतृत्व संभाल रहे दिग्गजों का कद इतना बड़ा है और उनकी राजनीतिक दृष्टि इतनी प्रखर और मुखर है कि कोई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि वर्ष 2014 के बाद राज्य की बागडोर थामने वाले किसी भी मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाई है।

लेकिन यदि गुजरात के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो इन दिनों मुख्यमंत्री के मुकाबले उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ज्यादा सुर्खियों में नजर आते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हर्ष को पार्टी हाईकमान का सबल वरदहस्त प्राप्त है। कभी वे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में विदेशी मेहमानों के साथ नजर आते हैं। दूसरी ओर, विदेशों में होने वाले आयोजनों में गुजरात का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। कभी जापान में संपन्न एशियाई खेलों में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते दिखते हैं, तो कभी विदेशी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बांटते नजर आते हैं। उन्हें पिछले साल राज्य में सरकार बनने के तीन साल बाद सभी मंत्रियों से इस्तीफा दिलाकर गठित की गई नई टीम में अचानक उपमुख्यमंत्री का दायित्व सौंप दिया गया। सिर्फ चालीस साल की उम्र में उपमुख्यमंत्री बनने वाले वे राज्य के पहले राजनेता हैं। संघवी ने जब भाजपा में राजनीतिक सक्रियता शुरू की, तब वे महज पंद्रह साल के थे।

प्रशासनिक कामकाज से इतर संघवी विदेशी मेहमानों, देश के शीर्ष कारोबारियों तथा राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ संवाद करते नजर आते हैं। संघवी का ताल्लुक एक हीरा कारोबारी परिवार से है। राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि भाजपा को निकट भविष्य में राज्य की बागडोर थामने वाला हीरा मिल गया है। हर्ष संघवी छात्र जीवन से ही राजनीति में पदार्पण कर चुके थे। संघवी वर्ष 2008 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के प्रदेश महासचिव नियुक्त किए गए। साल 2010 में उन्हें पुन: संगठन में यही जिम्मेदारी मिली। 2011 में वे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। फिर 2013 में भाजपा के राष्ट्रीय युवा मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री भी बने। कालांतर में, 2014 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उनकी ताजपोशी हुई। इस तरह सीढ़ी-दर-सीढ़ी चढ़ते हुए वे लगातार रसूखदार नेता बनते चले गए। हर्ष रमेश कुमार संघवी ने साल 2012 में सूरत की मजूरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा तो वे राज्य में सबसे कम उम्र में विधानसभा पहुंचने वाले राजनेता बने। फिर 2017 और 2022 में लगातार दूसरी और तीसरी बार विधायक बने। हर बार उनकी जीत का प्रतिशत बहुत अधिक रहा। उनके राजनीतिक रसूख का पता इस बात से चलता है कि उपमुख्यमंत्री के अलावा उनके पास एक दर्जन से अधिक मंत्रालयों का दायित्व है। निस्संदेह, वे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गुडबुक में हैं। यही वजह है कि उपमुख्यमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व के सामने मुख्यमंत्री का आभामंडल फीका लगता है।

नि:संदेह, हर्ष संघवी गुजरात में बेहद लोकप्रिय हैं, जिसमें उनके आकर्षक व्यक्तित्व की भी भूमिका है। बताते हैं कि पिता के हीरा कारोबार में हाथ बंटाते-बंटाते वे सिर्फ आठवीं कक्षा तक ही पढ़ पाए। लेकिन उनका राजनीतिक कौशल और वाकपटुता ज्यादा पढ़े-लिखे लोगों पर भारी पड़ती है। यही वजह है कि हर्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आंखों का तारा बने हुए हैं। राज्य में सबसे कम उम्र में उपमुख्यमंत्री बनने वाले संघवी राज्य में भाजपा का भविष्य का चेहरा हैं। वे राज्य के छठे उपमुख्यमंत्री हैं। उनकी राजनीतिक पारी लंबी होने वाली है।

दरअसल, जैन समुदाय से आने वाले हर्ष संघवी हीरा कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता रमेश संघवी का नाम गुजरात के बड़े हीरा व्यापारियों में शुमार रहा है। उनकी मां का नाम देवेंद्रबेन संघवी है। उनकी पत्नी का नाम प्राची है, जो गृहिणी हैं। उनकी दो संतानें हैं। बेटे का नाम आरुष और बेटी का नाम निरवा है। हर्ष गुजरात के लोकप्रिय नेता हैं। गुजरात की राजनीति में उनके रसूख का पता इस बात से चलता है कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अडानी भी उनके घर पहुंचे थे। उनकी पहचान एक समाजसेवी के रूप में भी रही है। समाजसेवा के शुरुआती दिनों में उन्होंने युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर, करियर मार्गदर्शन शिविर और विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। विभिन्न आदिवासी जिलों में फैले सिकल सेल और एनीमिया जैसे रोगों के उन्मूलन के लिए चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया।

निस्संदेह, गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में उनकी अति-सक्रियता देखकर अंदाजा लगाना कठिन नहीं है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बहुत संभव है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें राज्य का नेतृत्व करने का मौका दे दे।

कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद बाकी सवाल

इन्द्रजीत सिंग

किसान आंदोलन की वर्षगांठ

साल 2020 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन आखिर उन्हें वापस कराने में सफल रहा। उस जीत को 26 नवंबर को वर्षगांठ के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि आज छह साल बाद भी एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मामले अनसुलझे हैं।

छब्बीस नवंबर को किसान आंदोलन की छठी वर्षगांठ है। यह वही आंदोलन था, जो केंद्र सरकार द्वारा 5 जून, 2020 को जारी किए गए तीन कृषि अध्यादेशों के खिलाफ लगभग 13 महीने तक चला। इन अध्यादेशों को संसद में आनन-फानन में पारित करवाकर तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर 27 सितंबर, 2020 को कानून का रूप दे दिया गया था।

वहीं, 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। उल्लेखनीय है, इसी समय संसद ने चार श्रम संहिताएं (लेबर कोड) भी पारित की थीं, जिनके जरिये दशकों से प्रचलित समूचे श्रम कानूनों को बदल दिया गया।

तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को किसान विरोधी, कॉर्पोरेट हितैषी तथा समूची कृषि व्यवस्था के लिए विनाशकारी माना गया। इन कानूनों का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देकर निजी कंपनियों के निर्बाध प्रवेश की राह खोलना तथा खाद्यान्न व्यापार में एकाधिकार को प्रोत्साहित करना था। इनके दूरगामी परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोनों पर पड़ने निश्चित थे। किसान पहले ही कृषि लागत में लगातार वृद्धि व आय में ठहराव के कारण प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे।

25 नवंबर को पंजाब-हरियाणा के लाखों किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच शुरू किया। उन्होंने हरियाणा की तत्कालीन गठबंधन सरकार द्वारा किए गए पुलिस दमन का मुकाबला किया। दिल्ली के सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर 26 नवंबर को मोर्चे लगने से राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। इसी दिन चार श्रम संहिताओं के खिलाफ औद्योगिक और ट्रेड यूनियन मजदूरों ने भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए। कई किसान संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का गठन किया गया।

आंदोलन की पहली प्रमुख विशेषता मुद्दों पर आधारित एकता थी। तीनों कृषि कानून ऐसे थे, जो किसान समुदाय के सभी वर्गों को प्रभावित कर रहे थे। दूसरी विशेषता थी कि कोविड महामारी सहित मौसम की प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए किसानों ने सीमाओं पर डेरे डाले रखे। तीसरी विशेषता थी महिलाओं की विशाल भागीदारी। चौथी विशेषता थी आंदोलन को मिला व्यापक जनसमर्थन, विशेषकर हरियाणा से, जिसकी भौगोलिक स्थिति तीन ओर से राष्ट्रीय राजधानी को छूती है। इनके अलावा, हरियाणा व पंजाब के अनेक टोल प्लाजा पर भी समर्थन में धरना स्थल बने रहे और टोल टैक्स बंद रहे।

किसान आंदोलन की खास बात थी कि धरना स्थलों पर राष्ट्रीय दिवसों और त्योहारों को गरिमा के साथ मनाया जाता था। शासन द्वारा आंदोलन को राष्ट्रविरोधी करार देने के प्रयास किए गए। पंजाब और हरियाणा के किसानों के



बीच क्षेत्रीय भावनाएं भड़काने के लिए एसवाईएल का मुद्दा भी उछाला गया। लेकिन हथकंडे बेअसर रहे। आम लोगों, विशेषकर बेरोजगारी से जूझ रहे ग्रामीणों के बीच शासन की छवि 'अहंकारी' बन रही थी।

ऐसी स्थितियों में केंद्र को 19 नवंबर को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन वापस लेने को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा अन्य प्रमुख मांगों पर भी लिखित आश्वासन की शर्त रखी।

अंतत: 9 दिसंबर, 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लिखित रूप में पत्र जारी किया। साथ ही अन्य अधिकांश मांगों पर भी सकारात्मक रुख दिखाया, जिनमें सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी की मांग भी शामिल थी।

हालांकि, विभिन्न सरकारों ने किसान आंदोलन से शायद ही कोई सबक सीखा। वे उन्हीं जनविरोधी नीतियों को आगे बढ़ाते रहे। मसलन, बीज संशोधन विधेयक, बिजली संशोधन विधेयक, सहकारी कानून में प्रतिगामी संशोधन। वहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सी-2+50 प्रतिशत के फार्मूले पर एमएसपी तय करने की मांग की अनदेखी की। हालांकि इसका राजनीतिक परिणाम भी सामने आया मसलन, भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में विफल रही!

वर्ष 2022 से संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को देशभर में विभिन्न रूपों में एक विशेष दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस बार भी देशभर में किसान लामबंदी की जा रही है। इसके पीछे दो अतिरिक्त अहम कारक जुड़े हैं। पहला, देश में जारी एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग के भीतर से ही इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए। दूसरा, 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वे बयान हैं, जिनमें उन्होंने कॉर्पोरेट जगत पर आरोप लगाया कि वह भारी वित्तीय लाभ अर्जित कर रहा है, लेकिन बदले में रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं कर रहा। यह एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म नीति की स्वीकारोक्ति का मामला है, जिस संबंधी आरोप किसान आंदोलन केंद्र पर लगाता आया है।

लेखक अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

भिलाई-3 में बनेगा मॉडल उप पंजीयक कार्यालय भवन

भिलाई। दुर्ग जिले के अनुविभाग मुख्यालय भिलाई-3 में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। 71.41 लाख रूपये लागत की इस भवन का भूमिपूजन 24 नवम्बर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के करकमलों से संपन्न हुआ था। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के कार्यपालन अभियंता आरके गोडबोले ने बताया कि उक्त निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ गृह निर्माण भवन अधोसंरचना विकास मण्डल को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। संभाग कार्यालय द्वारा निविदा प्रकाशन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए, मेसर्स कौशल चन्द्राकर को भवन निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल भिलाई-3 में मॉडल उप पंजीयक कार्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया हैं। इस मॉडल ऑफिस में आम जनता को टोकन डिस्प्ले की सुविधा के साथ बैठने, वासरूम, पेयजल आदि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहेगी।

श्रमिकों की सुविधा के लिए नगरीय निकायों में स्थापित होंगे श्रमिक सहायता काउंटर

भिलाई। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिले के असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का त्वरित लाभ दिलाने तथा पंजीयन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए जिले के नगरीय निकायों के प्रमुख वार्डों एवं सार्वजनिक स्थलों पर श्रमिक सहायता काउंटर स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। श्रमिक सहायता काउंटर के माध्यम से पात्र निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों का नवीन पंजीयन, श्रमिक कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता एवं मोबाइल नंबर संबंधी त्रुटियों का सुधार और पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन प्राप्त कर उनका निराकरण एवं पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने की व्यवस्था भी की जाएगी।

शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा का प्रशिक्षण

भिलाई। शासकीय विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा को ऑनलाइन एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से 26 नवंबर को रूंगटा डेंटल कॉलेज में जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में जिले के लगभग 150 शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों ने सहभागिता की। प्रशिक्षण के दौरान स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा के ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं संबंधित कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही उपस्थित समस्त प्राचार्यों का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन तथा फिजिकल सिग्नेचर अपलोड करने का कार्य भी संपन्न कराया गया, आगे विद्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

सेल चेयरमैन ट्रॉफी फॉर यंग मैनेजर्स 2025-26 पर भिलाई इस्पात संयंत्र का कब्जा

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। सेल स्तर पर आयोजित प्रतिष्ठित चेयरमैन ट्रॉफी फॉर यंग मैनेजर्स (सीटीवाईएम) 2025-26 में भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता का अंतिम चरण 25 नवंबर 2026 को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची में आयोजित किया गया, जिसमें सेल की विभिन्न इकाइयों एवं एकीकृत इस्पात संयंत्रों की चयनित टीमों ने अपने तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत किए।

भिलाई इस्पात संयंत्र की विजेता टीम में सहायक महाप्रबंधक अरिंदम कर, वरिष्ठ प्रबंधक (एसएमएस-2) अनूप कुमार सिंह एवं वरिष्ठ प्रबंधक (एसएमएस-2) के पवन कुमार शामिल हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित चेयरमैन ट्रॉफी जीतकर संयंत्र को गौरवान्वित किया है। इस वर्ष प्रतियोगिता की थीम 'वर्किंग टुगेदर एज वन सेल : कोलैबोरेट, परफॉर्म एंड एक्सेल' रखी गई थी। प्रतियोगिता का उद्देश्य अध्ययन एवं प्रबंधन संबंधी अवधारणाओं के माध्यम से युवा प्रबंधकों में आत्मविश्वास, प्रबंधकीय क्षमता एवं सामूहिक कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करना है।

सेल में 45 वर्ष तक की आयु के अधिकारी इसमें भाग लेने के पात्र हैं। विजेता टीम के प्रत्येक सदस्य को 30,000 रुपये की नकद पुरस्कार राशि के साथ विदेशी इस्पात संयंत्र के तीन दिवसीय भ्रमण का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में बोकारो इस्पात संयंत्र की टीम प्रथम उपविजेता तथा इस्को इस्पात संयंत्र की टीम द्वितीय उपविजेता रही।

उल्लेखनीय है कि बीएसपी की टीमें अब तक 10 बार इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी पर कब्जा कर चुकी हैं तथा 7 बार उपविजेता रही हैं। इस प्रकार अब तक आयोजित 22 प्रतियोगिताओं में से 17 बार बीएसपी की टीमों ने शीर्ष दो स्थानों पर अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धि शीर्ष प्रबंधन के सतत प्रोत्साहन और मानव संसाधन-विकास एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा युवा प्रबंधकों को दिए जा रहे मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण को दर्शाती है।

संविधान दिवस पर न्यायालयों व कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन

न्यायाधीश, युवा अधिवक्ता, विधि विद्यार्थियों एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने की सहभागिता

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। भारतीय संविधान के अंगीकरण की स्मृति में गुरूवार को संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में जिले के विभिन्न न्यायालयों, विधि महाविद्यालयों एवं अन्य स्थानों पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन तथा विधिक जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के विनोद कुजूर तथा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर की विशेष उपस्थिति में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीशगण एवं युवा अधिवक्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विशेष रूप से युवा अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी ने संविधान के प्रति उनकी आस्था, विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्धता तथा न्यायिक व्यवस्था के मूल्यों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित किया।

इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा की विशेष उपस्थिति में भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया।

इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत के न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान में निहित मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड में भी श्रीमती कामिनी जायसवाल की विशेष उपस्थिति में भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया तथा संविधान में निहित मूल आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

विधि विद्यार्थियों के बीच संवैधानिक मूल्यों का संदेश

संविधान दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए सुराना लॉ कॉलेज एवं कल्याण लॉ कॉलेज में भी न्यायाधीशगण द्वारा विधिक जनजागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता की गई। इन कार्यक्रमों में विधि विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की महत्ता, प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों तथा न्याय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता के महत्व से अवगत कराया गया। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि विधि का अध्ययन केवल कानूनी प्रावधानों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता, न्यायप्रियता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने आचरण में अपनाना भी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को संविधान के मूल आदर्शों एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई।

बैगा पारा में 18.24 लाख रुपए से होगा सड़क का डामरीकरण, लोक कर्म प्रभारी ने किया निरीक्षण



श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम महापौर अलका बाघमार के निर्देश पर आज वार्ड क्रमांक 9 बैगा पारा में सड़क डामरीकरण कार्य को लेकर आज लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर एवं सभापति श्याम शर्मा द्वारा एमआईसी सदस्य शेखर चन्द्राकर एवं ज्ञानेश्वर ताम्रकर, पार्षद जीतू ताम्रकर, कार्यपालन अभियंता मोहम्मद सलीम सिद्दीकी, सहायक अभियंता संजय ठाकुर एवं उप अभियंता करण यादव के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण किया।

गोपाल मंदिर से चंद्राकर ट्रेडर्स, बैगा पारा स्टेडियम के समीप तक सड़क का बीटी रिन्यूवल (डामरीकरण) कार्य 18.24 लाख रुपये की लागत से कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्थल की स्थिति, साफ-सफाई एवं निर्माण कार्य की तैयारियों का जायजा लिया। लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर ने सड़क निर्माण क्षेत्र में बाधा बन रहे सड़क किनारे रखे बिल्डिंग मटेरियल,सहित पुराने कबाड़ गाड़ीयो एवं ठेले को हटाने की अपील करते हुए कहा कि निर्माण कार्य सुचारू रूप से पूरा कराने में नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अमृत सरोवरों में गूंजा संविधान का संदेश, ग्रामीणों ने लिया जल संरक्षण और सामाजिक समरसता का संकल्प

श्रीकंचनपथ न्यूज



दुर्ग। संविधान दिवस के अवसर पर जिले के अमृत सरोवरों में संविधान के आदर्शों के साथ जल संरक्षण और सामाजिक समरसता का संदेश गूंजा। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को संविधान में निहित अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने संविधान की प्रस्तावना के आदर्शों का पालन करने के साथ-साथ जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और सामाजिक एकता बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया।

जनपद पंचायत पाटन की ग्राम पंचायत जरवाय, देमार, टेमरी, बोरवाय एवं भनसुली, जनपद पंचायत दुर्ग की ग्राम पंचायत थनौद तथा जनपद पंचायत धमधा की ग्राम पंचायत दरगांव एवं सेवती में ग्रामीणों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंचगण एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रमों में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर उसके मूल आदर्शों के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली। अमृत सरोवरों के परिसर में आयोजित कार्यक्रमों को जल संरक्षण से जोड़ते हुए ग्रामीणों ने तालाबों एवं सार्वजनिक जल संरचनाओं को स्वच्छ रखने, जल का अपव्यय रोकने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने तथा जल स्रोतों के रखरखाव में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया।

ब्लैक आउट में नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को परखने दुर्ग में मॉक ड्रिल अभ्यास

श्रीकंचनपथ न्यूज



दुर्ग। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज शाम जिला प्रशासन एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त तत्वावधान में सफल मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया। यह अभ्यास गुरूवार की शाम 05 बजे से रात्रि 07 बजे तक केंद्रीय विद्यालय के पास स्थित डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट दुर्ग कैंपस में आयोजित हुआ। वहीं शाम 6.30 बजे 05 मिनट के लिए ब्लैकआउट अभ्यास किया गया।

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार आयोजित इस मॉक ड्रिल में सभी संबंधित विभागों ने अपने निर्धारित दायित्वों का मुस्तैदी से निर्वहन किया। अभ्यास के दौरान आपात स्थिति का सायरन बजने के साथ ही आकस्मिक आपदा या संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय को परखा गया। संयुक्त मॉक ड्रिल से प्रशासनिक अमले और सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित समन्वय मजबूत होता है तथा वास्तविक परिस्थितियों में कम से कम समय में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सकता है। हवाई आक्रमण से बचने ब्लैकआउट मॉकड्रिल भी किया गया।

इस संयुक्त अभ्यास में एसएसपी दुर्ग, सीएसपीडीसीएल, फायर ब्रिगेड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मेडिकल टीम, तहसीलदार तथा फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इसके साथ ही एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने भी राहत, बचाव एवं भीड़ नियंत्रण की व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

अभ्यास के दौरान अग्निशमन, प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी और विभिन्न एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल का जीवंत प्रदर्शन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभ्यास की समीक्षा करते हुए कहा कि इस प्रकार के नियमित मॉक ड्रिल से न केवल विभागीय तैयारियों की परख होती है, बल्कि आम नागरिकों में भी आपात स्थितियों के प्रति जागरूकता और सतर्कता बढ़ती है।

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में मनाया गया संविधान दिवस

संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप आचरण एवं कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

श्रीकंचनपथ न्यूज



दुर्ग। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में आज संविधान दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. संजय तिवारी ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना के मूल आदर्शों के अनुरूप आचरण करने तथा अपने संवैधानिक एवं नैतिक दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर कुलपति प्रो. डॉ. संजय तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार एवं समान अवसर प्रदान करता है। संविधान धर्म, जाति, लिंग अथवा किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व भारतीय संविधान के मूल आधार स्तंभ हैं। इन आदर्शों को केवल औपचारिक रूप से अंगीकार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन के व्यवहार में भी आत्मसात करना आवश्यक है। उन्होंने सभी से संविधान में निहित मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, निष्पक्षता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. डॉ. अनिल कुमार पांडेय ने भारतीय संविधान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा के योगदान तथा संविधान में समाहित लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं सामाजिक समरसता का आधार है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने की अपील की।

कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय परिवार ने संविधान में निहित आदर्शों एवं मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक न्यायपूर्ण, समतामूलक एवं समरस समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया।

कलेक्ट्रेट में संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन

संविधान दिवस के अवसर पर आज कलेक्टोरेट, तहसील एवं ग्राम स्तर सहित शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, नगरीय निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों एवं संगठनों में भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया। इस दौरान अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर संविधान के मूल आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह, जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे, नगर निगम दुर्ग आयुक्त लीना कोसम, नगर पालिक निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा आदि उपस्थित रहे।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास खबर

छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की अवसर परीक्षाएं 14 दिसंबर से समय-सारिणी जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं चतुर्थ अवसर परीक्षाओं की समय-सारिणी जारी कर दी गई है। परीक्षाएं 14 दिसंबर से प्रारंभ होकर 22 दिसंबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने बताया कि हाईस्कूल पत्राचार पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं चतुर्थ अवसर परीक्षा के अंतर्गत 14 दिसंबर को सामान्य अंग्रेजी एवं संस्कृत, 15 दिसंबर को सामान्य हिन्दी, 16 दिसंबर को विशिष्ट उर्दू, 17 दिसंबर को गणित, 19 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान तथा 21 दिसंबर को विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित होगी। हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं चतुर्थ अवसर परीक्षा के तहत 14 दिसंबर को विशिष्ट उर्दू, 15 दिसंबर को राजनीति शास्त्र, 16 दिसंबर को समाजशास्त्र, 17 दिसंबर को रसायन शास्त्र, लेखाशास्त्र एवं इतिहास, 19 दिसंबर को व्यवसाय अध्ययन, गणित, जीव विज्ञान एवं भूगोल, 21 दिसंबर को अर्थशास्त्र एवं भौतिकी तथा 22 दिसंबर को सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी विषय की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

पावर कंपनियों में 1,501 पदों पर भर्ती के लिए डेढ़ लाख से अधिक आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज की तीनों कंपनियों में 1,501 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लगभग डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर 2026 की रात 11.55 बजे तक कर दी गई है। इस समय तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी में कुल 1,501 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इनमें द्वितीय श्रेणी के 195 तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 1,306 पद शामिल हैं। विस्तृत भर्ती विज्ञापन पावर कंपनी की वेबसाइट **https//cspc.co.in** पर उपलब्ध है। भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के अंतर्गत 38 प्रकार के पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें सबसे अधिक आवेदन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त हुए हैं।

सेवा सेतु केंद्र से गुमेन्द्र को मिली बड़ी राहत, 5-6 वर्षों बाद बना स्थाई जाति प्रमाण पत्र

नारायणपुर। शासन की जनकल्याणकारी सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, सहज और त्वरित रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु पहल लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सेवा सेतु के माध्यम से अब ऐसे नागरिकों को भी शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है, जो लंबे समय से आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में परेशानियों का सामना कर रहे थे। इसी कड़ी में छोटेडोंगर के सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से गुमेन्द्र पिता भानसिंह को स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जिससे उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा है। गुमेन्द्र पिछले 5 से 6 वर्षों से स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रयासरत थे। प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया एवं आवश्यक जानकारी के अभाव में उन्हें बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

संविधान के आदर्शों पर चलकर विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रही हमारी सरकारः मुख्यमंत्री साय

जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों पर नहीं पड़ेगा समान नागरिक संहिता का प्रभाव

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारा संविधान केवल अधिकारों और कर्तव्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित सशक्त राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक है। संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहाँ प्रत्येक नागरिक को सम्मान, समान अवसर और विकास में भागीदारी मिले। हमारी सरकार इन्हीं संवैधानिक मूल्यों को सुशासन का आधार बनाकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।





लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए संघर्षों को याद रखना जरूरी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार हमारे संविधान की अमूल्य देन हैं। उन्होंने वर्ष 1975 के आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में नागरिक स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी पर प्रतिबंध लगाए गए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अपने पारिवारिक अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके बड़े पिताजी नरहरि साय लोकतंत्र सेनानी थे और आपातकाल के विरोध में उन्हें 19 महीने जेल में रहना पड़ा। इस दौरान परिवार को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों का त्याग और संघर्ष हमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रति सदैव सजग रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को आपातकाल के इतिहास से परिचित कराने के उद्देश्य से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में पूर्व में बंद की गई सम्मान राशि को पुनः प्रारंभ किया है।

संविधान की लोककल्याणकारी भावना को धरातल पर उतार रही सरकार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे लोककल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की थी, जहाँ विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसी भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और जनजातीय समाज के सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी की जा रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान की जा रही है। महतारी वंदन योजना से लाखों महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। जनजातीय समाज को वनोपज का बेहतर मूल्य दिलाने, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की सार्थकता तभी है, जब उसके आदर्श हमारे निर्णयों और कार्यों में दिखाई दें। हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास की यात्रा में कोई भी वर्ग और कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे।

न्याय और सुशासन की भावना को मजबूत कर रही सरकारः गजेंद्र यादव

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि संविधान समय और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप देश को आगे बढ़ने की दिशा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू करना न्याय व्यवस्था में दृष्टिकोण के परिवर्तन का प्रतीक है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें प्रत्येक नागरिक के अधिकार सुरक्षित हों और आमजन को सहजता से न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी जनहितकारी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से संविधान की मूल भावना को साकार कर रही है।

समान नागरिक संहिता से सुरक्षित रहेंगी जनजातीय परंपराएँ

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में समानता और नागरिक अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और तीन तलाक के विरुद्ध कानून बनाए जाने का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में समिति का गठन किया गया है। उन्होंने जनजातीय समाज की आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों से इन परंपराओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सहित सभी संविधान निर्माताओं के अमूल्य योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब के जीवन, विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। साथ ही श्संविधान से सुशासन तक रू बाबा साहेब के सपनों का सशक्त छत्तीसगढ़श् पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वर्ष 2015 से संविधान दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिससे नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को संविधान के आदर्शों और अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने का अवसर मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार, सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का आसीन होना इसी भावना का सशक्त उदाहरण है। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और लोकतंत्र में उपलब्ध समान अवसरों की प्रेरणादायी मिसाल है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद ने लंबे समय तक बस्तर में लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास को चुनौती दी। नक्सली गणतंत्र के स्थान पर गनतंत्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन बस्तर की जनता ने लोकतंत्र के प्रति अपनी अटूट आस्था बनाए रखी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में मतदान कर लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई हुई है। सुरक्षाबलों के साहस और सुनियोजित रणनीति से बस्तर में शांति, सुरक्षा और विकास के नए अवसर निर्मित हो रहे हैं। अब दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि संविधान गौरव दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और स्वाभिमान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की गौरवशाली विरासत और महान विभूतियों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए अनेक पहल की गई हैं। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों के विकास का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे उनके विचारों और योगदान को व्यापक पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के साथ कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करता है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण में योगदान देने वाले ज्ञात-अज्ञात महानायकों के संघर्ष और बलिदान से नई पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, विधायक सुनील सोनी सहित जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

खेल के मैदान में दिखा युवा जोश और प्रतिभा का शानदार संगम, फुटबॉल खिलाड़ियों ने बांधा समां

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, अनुशासन, उत्साह एवं सामूहिक खेल भावना से मैदान में रोमांच भर दिया।

मंत्री अग्रवाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी प्रतिभागियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का सशक्त माध्यम हैं। खेल न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और संघर्ष करने की भावना भी विकसित करते हैं। खेल के मैदान में अर्जित अनुभव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि फुटबॉल जैसे सामूहिक खेल आपसी



सहयोग, समन्वय, एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत बनाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और खेल भावना को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। युवाओं को अपनी मेहनत, लगन और समर्पण के बल पर खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरगुजा अंचल में खेल प्रतिभाओं की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय स्तर पर इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन उभरती खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रदेश में सड़कों की स्थिति की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक से मजबूत होगी निगरानी व्यवस्था

प्रदेश की 150 से अधिक सड़कों का वीडियो आधारित सर्वेक्षण कर ऐप की टेस्टिंग करने के दिए निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नियमित रखरखाव एवं निगरानी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने आज रोड कंडीशन ट्रैकिंग ऐप की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने ऐप की कार्यप्रणाली, तकनीकी विशेषताओं एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की।

अधिकारियों ने बताया कि ऐप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण की सभी सड़कों को शामिल किया गया है। ऐप के माध्यम से सड़कों की वास्तविक स्थिति की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अंतर्गत सड़कों का वीडियो तैयार कर उसे दिनांक, समय एवं जियो लोकेशन के साथ ऐप में अपडेट किया जाएगा। सड़कों पर स्थित गड्ढों, क्षतिग्रस्त हिस्सों एवं अन्य समस्याओं को भी मैप किया जाएगा। सड़कों की वस्तुस्थिति की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेज का भी उपयोग किया जाएगा।

हर छह माह में होगा सड़कों का सर्वेक्षण

अधिकारियों ने बताया कि ऐप के माध्यम से प्रत्येक छह माह में सड़कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में सर्वेक्षण नहीं होने की स्थिति में ऐप में स्वतः अलर्ट जारी होगा, जिससे संबंधित अधिकारियों को लंबित सर्वेक्षण की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे सड़कों की नियमित निगरानी एवं रखरखाव की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

इस ऐप के माध्यम से किसी भी सड़क के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी स्थिति की तत्काल निगरानी की जा सकेगी। इससे सड़क संबंधी समस्याओं की पहचान करने, आवश्यक मरम्मत कार्यों का निर्धारण करने तथा शिकायतों के समयबद्ध निराकरण में सहायता मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश की 150 से अधिक सड़कों का वीडियो तैयार कर उनका सर्वेक्षण करने तथा ऐप की सभी तकनीकी विशेषताओं का व्यापक परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऐप के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन की शीघ्र भर्ती एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मॉनिटरिंग में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं की पहचान कर उसके निराकरण के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक अश्वनी देवांगन, मुख्य अभियंता के.के. कटारे सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बिहान से बदली गायत्री की जिंदगी, खेती और मछली पालन से बनीं लखपति दीदी

मेहनत, लगन और उन्नत कृषि तकनीक से लिख रहीं आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सशक्त माध्यम बन रहा है। महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और उद्यमशीलता से सफलता की नई कहानियां भी लिख रही हैं।



गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम पंचायत विषेशरा की गायत्री उइके ने खेती और मछली पालन को अपनी आजीविका का आधार बनाकर लखपति दीदी बनने का सपना साकार किया है। उनकी यह उपलब्धि अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रही है। ग्राम पंचायत विषेशरा में गंगा महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी श्रीमती गायत्री उइके ने विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपनी आजीविका के साधनों का विस्तार किया है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित डबरी में मछली पालन के साथ ही उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाकर सब्जी उत्पादन शुरू किया। मचान एवं मल्चिंग विधि से बरबटी, लौकी और मटर की खेती कर वे अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। खेती और मछली पालन के समन्वय से उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाकर लखपति दीदी बनने की उपलब्धि हासिल की है। गायत्री उइके की सफलता इस बात का उदाहरण है कि उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और शासकीय योजनाओं के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। एक से अधिक आजीविका गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही परिवार की खुशहाली में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बिहान के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत कुदारी में भी एकीकृत कृषि समूह के तहत महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य जिमीकंद का उत्पादन कर आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्नत कृषि पद्धतियों और विविध आजीविका गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के लिए आय के नए रास्ते खुल रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उनके कौशल विकास, उद्यमशीलता और आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि, सब्जी उत्पादन एवं मछली पालन जैसी गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही महिला सशक्तीकरण का आधार बन रही हैं। लखपति दीदी बनीं श्रीमती गायत्री उइके की सफलता ग्रामीण महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। उनकी उपलब्धि यह संदेश देती है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, निरंतर परिश्रम, उन्नत तकनीक और शासकीय योजनाओं के बेहतर उपयोग से आर्थिक समृद्धि की राह प्रशस्त की जा सकती है।







जयपुर की सैर पर निकलीं 'खतरों के खिलाड़ी 15' की प्रतियोगी रुहानिका

टीवी अभिनेत्री रुहानिका धवन राजस्थान के जयपुर की सैर पर निकली हैं। अभिनेत्री ने अपने फैंस को अपनी छुट्टियां बिताने की झलकियां दिखाई हैं। उन्होंने कई शानदार पोज दिए हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक प्यारा कैप्शन लिखा है।

रुहानिका की पोस्ट में क्या है?

अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने लाइब्रेरी में और स्वीमिंग पूल के किनारे पोज दिए हैं। कई तस्वीरों में वह पिंक कलर के शॉर्ट आउटफिट में नजर आ रही हैं। यही नहीं अभिनेत्री ने एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया है।

यूजर्स ने की अभिनेत्री की तारीफ

इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री कैप्शन में लिखा, 'जयपुर की कुछ झलकियां आपके लिए। जयपुर तुम बहुत खूबसूरत हो।' रुहानिका की तस्वीरों को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि आप और ये जगह दोनों प्यारे हैं। कई दूसरे यूजर्स ने उन्हें क्यूट कहा है।

कौन हैं रुहानिका?

रुहानिका टीवी शो 'मिसेज कौशिक की पांच बहुएं', 'ये हैं मोहब्बतें' और 'मेरे साई- श्रद्धा और सबुरी' का हिस्सा रह चुकी हैं। वह शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' की प्रतियोगी थीं।

फिल्मों में किया काम

रुहानिका ने फिल्मों में भी काम किया है। वह सलमान खान की फिल्म 'जय हो' में कैमियो कर चुकी हैं। इसके अलावा 'घायल वंस अगेन' का भी हिस्सा रही हैं।

बेटे रियान के जन्म से एक रात पहले खूब रोई थीं जेनेलिया देशमुख, बोलीं- मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है

अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख ने बेटे रियान के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और उन पलों को याद किया, जब वह पहली बार मां बनने वाली थीं। उन्होंने बताया कि रियान के जन्म से एक रात पहले वह काफी भावुक हो गई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आने वाली जिंदगी कैसी होगी। उस रात वह अपने पति और अभिनेता रितेश देशमुख के गले लगकर काफी रोई थीं। जेनेलिया ने इंस्टाग्राम पर रियान के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए 24 नवंबर की रात का जिक्र किया।



उन्होंने लिखा, "मुझे आज भी 24 नवंबर की रात याद है। मैं प्रेग्नेंसी के आखिरी दौर में थी और मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा 25 नवंबर को इस दुनिया में आएगा। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसका असल मतलब क्या है। उस रात मैं तुम्हारे बाबा की बाहों में खूब रोई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे लिए क्या होने वाला है।" जेनेलिया ने आगे बताया कि उस दिन सिर्फ रियान का ही जन्म नहीं हुआ था, बल्कि उसी दिन उनका भी एक नए रूप में जन्म हुआ था। वह मां बनी थीं और यह पल उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया।

उन्होंने लिखा, "फिर 25 नवंबर आया और एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, साथ ही एक मां का भी जन्म हुआ। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि यह दिन मेरे लिए कितना मायने रखता है, लेकिन शायद मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यह मेरी और तुम्हारे बाबा की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है।"

जेनेलिया ने अपने पोस्ट में बेटे के लिए प्यार जाहिर करते हुए आगे लिखा, "चाहे जिंदगी तुम्हें किसी भी हाल में और कहीं भी ले जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। तुमने मुझे आई का टाइटल दिया और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस टाइटल पर खरी उतरने की कोशिश करती रहूंगी।"

बता दें कि जेनेलिया और रितेश देशमुख ने साल 2012 में शादी की थी। शादी के करीब दो साल बाद 25 नवंबर 2014 को उनके घर पहले बेटे रियान का जन्म हुआ। इसके बाद जून 2016 में दोनों दूसरी बार माता-पिता बने और उनके छोटे बेटे राहिल का जन्म हुआ। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के साथ बिताए खास पलों की झलक शेयर करते रहते हैं।

नोरा फतेही के डांस का लगेगा जबरदस्त तड़का जॉन के साथ 6 साल बाद करेंगी वापसी



जॉन अब्राहम की फिल्म 'फोर्स 3' में नोरा की एंट्री खास होने वाली है। इसके साथ ही वह करीब छह साल बाद जॉन अब्राहम के साथ फिर से काम करती नजर आएंगी।

बड़े लेवल पर तैयार किया जाएगा गाना

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स इस गाने को बड़े लेवल पर तैयार करने का प्लान बना रहे हैं। फिल्म के एक्शन और बड़े दर्शक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इसे खास अंदाज में फिल्माया जाएगा। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया, 'नोरा को एक खास डांस नंबर के लिए चुना गया है। इसे हाई एनर्जी और शानदार म्यूजिकल अंदाज में तैयार करने का प्लान है, जो बड़े पर्दे पर दर्शकों का मनोरंजन करेगा।' हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इस गाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। गाने से जुड़ी बाकी जानकारियां फिलहाल सामने नहीं आई हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट और रिलीज डेट

भाव धूलिया के निर्देशन में बन रही 'फोर्स 3' में जॉन अब्राहम एक बार फिर एसीपी यशवर्धन सिंह के किरदार में दिखाई देंगे। फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2011 में 'फोर्स' से हुई इसके बाद 2016 में इसका दूसरा भाग 'फोर्स 2' रिलीज हुआ था।

फिल्म के तीसरे भाग में जॉन के साथ हर्षवर्धन राणे, तान्या मानिकतला और सूर्या शर्मा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'फोर्स 3' अगले साल 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ये प्रेम मोल लिया मूवी रिव्यू दिल छू लेने वाली है, आयुष्मान और शरवरी की जोड़ी



सादगी, ईमानदारी, पवित्रता, अच्छाई और परंपराएं—सूरज बड़जात्या ने 'ये प्रेम मोल लिया' में अपनी इन सभी खास खूबियों को एक साथ पिरोया है। यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों और इंसानी स्वभाव की अच्छाइयों का जश्न मनाती है। आज के दौर में, जब बॉक्स-ऑफिस पर बड़े इवेंट वाली फिल्मों का बोलबाला है, राजश्री प्रोडक्शंस की यह फिल्म आपको आपकी जड़ों, आपके संस्कारों और सबसे महत्वपूर्ण बात—उन भावनाओं की याद दिलाती है जो परिवारों को एक साथ बांधे रखती हैं।

भले ही फिल्म आपको कहानी में पूरी तरह शामिल करने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन यह आपको एक सुखद सरप्राइज दे सकती है। आखिरकार, भावनाओं की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए!

'ये प्रेम मोल लिया' फिल्म की कहानी

'ये प्रेम मोल लिया' एक बड़े परिवार, उसके रिश्तों, परंपराओं और शादी व साथ रहने के बदलते स्वरूपों के इर्द-गिर्द घूमती है। हालाँकि इस फिल्म में सूरज बड़जात्या की फिल्मों की खासियतें - जैसे शादी-ब्याह के जश्न, गाने, रोमांस, पारिवारिक मिलन और आपसी टकराव - मौजूद हैं, लेकिन साथ ही यह एक ऐसे अलग विषय को भी उठाती है जो समाज के स्थापित नियमों को चुनौती देता है। मूल रूप से, यह फिल्म साझेदारी, समानता और आपसी समझ के बारे में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है।

सूरज बड़जात्या 'ये प्रेम मोल लिया' के साथ अपनी जानी-पहचानी शैली में वापस लौटे हैं, और उन्होंने राजश्री के फॉर्मूले को बहुत खूबसूरती से अपनाया है। सादगी, ईमानदारी, पवित्रता, अच्छाई और परंपराएं इस कहानी का मुख्य आधार हैं। हालांकि, एक पारिवारिक मनोरंजन फिल्म के रूप में पेश की गई इस कहानी के भीतर एक प्रगतिशील सोच छिपी है, जो समाज की कुछ पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाती है और रिश्तों के बदलते स्वरूप को सामने लाती है।

फिल्म के पक्ष में जो बात जाती है, वह है पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाने की इसकी क्षमता। यह पारिवारिक रिश्तों और एक-दूसरे का साथ देने के महत्व को दर्शाती है, साथ ही इस बात पर भी जोर देती है कि रिश्ते बराबरी, समझ और आपसी सम्मान पर टिके होने चाहिए। अपनी पिछली फिल्मों की तरह, सूरज ने फिल्म के सबसे प्रभावशाली पलों को दूसरे हिस्से के लिए बचाकर रखा है। कहानी धीरे-धीरे आपको अपने साथ जोड़ लेती है, और इसके भावुक पल आखिर में आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं।

सुरभि होरो की पटकथा में कई बेहतरीन पल हैं। कोर्टरूम के दृश्य - एक बिल्कुल शुरुआत में और दूसरा क्लाइमेक्स से ठीक पहले - विशेष रूप से प्रभावशाली हैं। प्रार्थना सभा के दौरान स्वानंद किरकिरे का गुस्से में आ जाना भी एक यादगार पल है। 'तोरण' रस्म का महत्व भी उल्लेखनीय है, जिसे अनुपम खेर ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। ये दृश्य फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं और इसके मूल संदेश को और भी असरदार बनाते हैं।

हिमेश रेशमिया का संगीत इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। इसका साउंडट्रैक लाजवाब है, जिसमें टाइटल ट्रैक और 'झुमका पटोला' सबसे बेहतरीन हैं। ये दोनों गाने आसानी से याद रह जाते हैं और फिल्म के जश्न वाले माहौल को और बढ़ाते हैं। 'जय अम्बे बोल' और 'बुलाये छठी माँ' फिल्म की कहानी और इसके पारंपरिक आकर्षण को और भी निखारते हैं।

सभी कलाकारों का काम एक समान रूप से प्रभावशाली है। आयुष्मान खुराना बहुत सहजता से अपने किरदार में ढल जाते हैं। एक अभिनेता के तौर पर उनकी परिपक्वता साफ झलकती है, खासकर नाटकीय दृश्यों में, और उनका अभिनय बेहद शानदार है। शरवरी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और एक कलाकार के तौर पर उन्होंने भी बहुत प्रभावी काम किया है। उन्होंने अपने अभिनय की बेहतरीन रेंज दिखाई है और उन्हें पर्दे पर देखना बहुत सुखद लगता है।

अनुपम खेर बेहतरीन फॉर्म में हैं। वे अपने किरदार में भावनात्मक गहराई, विश्वास और आत्मीयता लाते हैं, और ऐसी अदाकारी पेश करते हैं जो केवल उनके स्तर का कलाकार ही कर सकता है। स्वानंद किरकिरे एक अहम भूमिका में सुखद सरप्राइज़ देते हैं और उनका काम एकदम शानदार है। गीता अग्रवाल शर्मा भी उतनी ही असरदार हैं और जब भी वे स्क्रीन पर आती हैं, तो छा जाती हैं।

सुप्रिया पाठक कपूर, सीमा पाहवा, सौम्या टंडन, सुरभि तिवारी, श्रुति सेठ, जमील खान, राजेश कुमार, गिरीश कुलकर्णी और शाद रंधावा फिल्म की पारिवारिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

लॉरेंस डिसूजा ने सुनाया मिथुन और श्रीदेवी से जुड़ा किस्सा, बोले- वह उनका इंतजार करते थे

अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं। वहीं उनके व्यक्तिगत जीवन भी फैंस के बीच चर्चा का विषय बना रहा। अब फिल्म निर्माता लॉरेंस डिसूजा ने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के बीच चर्चित रिश्ते के बारे में काफी कुछ बताया।

मिथुन-श्रीदेवी पर क्या बोले लॉरेंस?

लॉरेंस डिसूजा ने बीते जमाने की मशहूर जोड़ी मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बारे में अपनी यादें साझा कीं। उन्होंने सिद्धार्थ कन्नन के साथ हुई बातचीत में कहा, 'मिथुन या तो शूटिंग के दौरान या पैकअप के समय सेट पर आ जाते थे और श्रीदेवी के मेकअप रूम में उनका इंतजार करते थे। उस दौरान मिथुन योगिता बाली से शादीशुदा थे।' हालांकि, बाद में लॉरेंस ने स्पष्ट किया कि वह केवल वही बता रहे हैं जो उन्होंने सेट पर काम करते समय व्यक्तिगत रूप से देखा था।

80 के दशक की थी चर्चित जोड़ी

श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती 1980 के दशक की लोकप्रिय जोड़ी थी। उन्होंने 'जाग उठा इंसान' और 'वक्त की आवाज' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। उनके निजी रिश्तों को लेकर कई साल तक अटकलें सुर्खियों में रहीं। लेकिन दोनों में से किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों को स्वीकार नहीं किया। श्रीदेवी ने बाद में 1996 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी की। अभिनेत्री का फरवरी 2018 में दुबई में 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



मिथुन चक्रवर्ती का वर्कफ्रंट

मिथुन चक्रवर्ती 70 के दशक से ही लगातार अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं और आज भी कई बड़े प्रोजेक्टस हिस्सा हैं। वर्ष 2025 में वे 'श्रीमान वर्सेस श्रीमती', 'द बंगाल फाइल्स' और 'प्रजापति 2' जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जादू बिखेरते नजर आए थे। आने वाले समय में वे आमिर खान के बैनर तले बन रही और सनी देओल अभिनीत बहुचर्चित फिल्म 'बटवारा 1947' में एक विशेष भूमिका में रहे। इसके अलावा वह रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल 'जेलर 2' में एक विस्तृत कैमियो रोल में नजर आए।

खास-खबर

ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बनी किसानों के लिए राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों की सुविधा एवं आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी केंद्रों में की गई बेहतर व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह और खुशी का माहौल है। ऑनलाइन टोकन सुविधा, व्यवस्थित तौल एवं उपार्जन केंद्रों में उपलब्ध आवश्यक सुविधाओं से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की अपेक्षा अधिक सरल और सुविधाजनक हुई है। इसी कड़ी में जिले के ग्राम रतनपुर निवासी किसान ललित कुमार अपनी 30 क्विंटल धान की उपज लेकर रतनपुर धान उपार्जन केंद्र पहुंचे। उन्होंने ऑनलाइन टोकन सुविधा का लाभ लेते हुए निर्धारित तिथि पर अपनी उपज खरीदी केंद्र पहुंचाई। केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और सुव्यवस्थित खरीदी प्रक्रिया से प्रसन्न किसान ललित कुमार ने शासन की किसान हितैषी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए संतोष व्यक्त किया।

भारतीय भागीदारी विधेयक, 2026 के संबंध में बैठक आयोजित

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय भागीदारी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2026 के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधेयक के प्रस्तावित संशोधन के अनुमोदन के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव सुबोध कुमार सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. रोहित यादव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रजत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सौर ऊर्जा से जीवन में आया सकारात्मक बदलाव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं पहुंचविहीन वनांचल क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के माध्यम से इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के 14 ग्रामों के 18 मजराटोलों में निवासरत पहाड़ी कोरवा समुदाय के 171 परिवारों के घर सौर ऊर्जा से रोशन हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा इन सभी परिवारों के घरों में सोलर होम लाइट संयंत्र स्थापित कर सौर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कभी शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाने वाले इन घरों में अब सौर ऊर्जा की रोशनी पहुंच रही है। इससे बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और परिवार के अन्य दैनिक कार्यों में काफी सहूलियत मिल रही है। रोशनी मिलने के बाद रोजमर्रा के जीवन में काफी बदलाव आया है।

सुशासन से छत्तीसगढ़ में विकास का नया अध्याय : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सुशासन, जनकल्याण और समृद्धि के नए संकल्पों के साथ विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षों में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से जहां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हुए प्रदेश के तीन करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना है।

मुख्यमंत्री साय विशेष कार्यक्रम 'मुख्यमंत्री जी से संवाद छत्तीसगढ़ के विकास का विजन' में प्रदेश के विकास और भविष्य की कार्ययोजना पर अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों, प्रधानमंत्री की गारंटियों के क्रियान्वयन, औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, महिला सशक्तीकरण, कृषि विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार तथा बस्तर में शांति और विकास के नए दौर सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दिसंबर 2023 में सरकार गठन के साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने का कार्य प्रारंभ किया गया। पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। किसानों को दो वर्षों का लंबित धान बोनस प्रदान किया गया और 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की व्यवस्था लागू की गई। तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र हितग्राहियों तक सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर जैसे दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। गीदम में मेडिकल कॉलेज और जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का संचालन प्रारंभ हुआ है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से सुदूर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब खनिज आधारित पारंपरिक उद्योगों के साथ आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और रोजगार आधारित उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्रदेश को 8.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगभग 50 प्रतिशत निवेश परियोजनाएं आधुनिक तकनीक और अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश और कारोबार को सुगम बनाने के लिए 450 से अधिक सुधार किए गए हैं। दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026 और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर इकाई तथा देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त फार्मा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और रेडीमेड गारमेंट पार्क विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें उद्यमी और रोजगार प्रदाता बनाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के अंतर्गत पांच हजार स्टार्टअप प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बदलते औद्योगिक परिवेश और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप युवाओं को तैयार करने के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत प्रदेश की 30 आईटीआई का उन्नयन किया जा रहा है। छह शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों को सीजीआईटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एआई मिशन के माध्यम से 14 लाख विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

आजीविका डबरियों से बदलेगी गांवों की तस्वीर, लक्ष्य से 50 प्रतिशत ज्यादा हुआ निर्माण, अब 23 हजार को मंजूरी

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर । वीबी जीरामजी योजना अंतर्गत गांवों में अब पानी की हर बूंद समृद्धि का आधार बनने जा रही है। जल संरक्षण के साथ ग्रामीण महिलाओं और विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया आजीविका डबरी निर्माण अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। इस योजना के तहत जहां पिछले वर्ष 10 हजार डबरियां बनाने का लक्ष्य था, वहीं लक्ष्य से 50 प्रतिशत अधिक यानी 15 हजार डबरियों का निर्माण किया गया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 20 हजार डबरियों के लक्ष्य के मुकाबले वीबी जीरामजी योजना अंतर्गत अब तक 23 हजार से अधिक डबरियों को ग्रामसभाओं की मांग और अनुमोदन के बाद स्वीकृति मिल चुकी है। खास बात यह है कि इन डबरियों का निर्माण अंतर्गत सूचना पटल में महिलाओं के नाम लिखा जा रहा है यह निजी भूमि में किया जा रहा है, ताकि जल संरक्षण के साथ उन्हें अपनी परिसंपत्ति और आमदनी का स्थायी साधन भी मिल सके। इस पहल का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 दिसंबर 2025 को किया था।

कूच बेहार ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की दमदार शुरुआत

श्रीकंचनपथ न्यूज



भिलाई। बी.सी.सी.आई. द्वारा मेंस अंडर-19 कूच बेहार ट्रॉफी 2026 का आयोजन 26 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का पहला चार दिवसीय मुकाबला 26 से 29 नवंबर 2026 तक सेक्टर-10 मैदान, भिलाई में बड़ौदा अंडर-19 टीम के विरुद्ध खेला जा रहा है।

मुकाबले के प्रथम दिवस बड़ौदा अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दिन की समाप्ति तक 90 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बना लिए।

छत्तीसगढ़ की ओर से अमितेश मिश्रा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 81 रनों की पारी खेली। वहीं आदित्य यादव ने 75 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती प्रदान की। इनके अतिरिक्त वेदांश खेडीया ने 28 रन तथा अर्शवीर सिंह भाटीया ने नाबाद 27 रन बनाए।

बड़ौदा अंडर-19 की ओर से अनिकेत जोशी ने 3 विकेट प्राप्त किए, जबकि गौरव चौधरी ने 2 विकेट लेकर छत्तीसगढ़ की पारी को रोकने का प्रयास किया। पहले दिन की समाप्ति तक छत्तीसगढ़ ने 7 विकेट खोकर 295 रन बना लिए हैं। अमितेश मिश्रा और अर्शवीर सिंह भाटीया क्रीज पर नाबाद हैं। चार दिवसीय मुकाबले के आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ की टीम अपनी पहली पारी को और मजबूत करने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी।

विजय मर्चेंट ट्रॉफी: छत्तीसगढ़ ने बनाए 421 रन

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। बी.सी.सी.आई. द्वारा मेंस अंडर-16 विजय मर्चेंट मल्टी डे ट्रॉफी 2026 का आयोजन 14 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का तीसरा तीन दिवसीय मुकाबला 25 से 27 नवंबर 2026 तक लखनऊ में कर्नाटक अंडर-16 टीम के विरुद्ध खेला जा रहा है। मुकाबले के दूसरे दिवस कर्नाटक अंडर-16 टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ की टीम ने अपनी पहली पारी में 119.4 ओवरों में सभी 10 विकेट खोकर 421 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। छत्तीसगढ़ की ओर से आर्यन अग्रवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं आदित्य बैदवाल और केवल बैद अपने शतक से मात्र 1 रन दूर रह गए। दोनों बल्लेबाज 99-99 रन बनाकर आउट हुए। इनके अतिरिक्त उज्जवल मरकाम ने 75 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान अशुमन ठाकुर ने 33 रनों का योगदान दिया। कर्नाटक की ओर से भुवन गौडा और आयुष ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4-4 विकेट प्राप्त किए।

छत्तीसगढ़ के 421 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक अंडर-16 टीम ने दूसरे दिन की समाप्ति तक अपनी पहली पारी में 57 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए हैं।

कर्नाटक की ओर से रोहित रेड्डी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 119 रनों की शतकीय पारी खेली। उनके अतिरिक्त विआन जोशी ने नाबाद 52 रन तथा शिवराज ने 30 रनों का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की ओर से आदित्य बैदवाल ने 2 विकेट प्राप्त किए। दूसरे दिन की समाप्ति तक कर्नाटक की टीम छत्तीसगढ़ से 197 रन पीछे है। मुकाबले के तीसरे और अंतिम दिन छत्तीसगढ़ की टीम कर्नाटक की पारी को जल्द समेटने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरेगी।

विदर्भ ने छत्तीसगढ़ को 34 रनों से हराया

अमनदीप खरे की अर्ध-शतकीय पारी बेकार

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर। बी.सी.सी.आई. द्वारा सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी 2026-27 का आयोजन 14 नवंबर 2026 से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की टीम का छठवां मुकाबला 26 नवंबर 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में विदर्भ की टीम के विरुद्ध खेला गया। इस मुकाबले में विदर्भ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को 34 रनों से पराजित कर दिया।

मैच में विदर्भ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। विदर्भ की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 194 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। विदर्भ की ओर से अमन मोखाडे ने सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। उनके अतिरिक्त यश राठौर ने 39 रन, जबकि अथर्व और दानिश मालेवार ने 37-37 रनों का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ की ओर से विजय यादव, सौरभ मजुमदार, देव आदित्य सिंह और जयंत यादव ने 1-1 विकेट प्राप्त किया। 195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्तीसगढ़ की टीम 19.1 ओवरों में 160 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। छत्तीसगढ़ की ओर से अमनदीप खरे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक 62 रन बनाए।

उनके अतिरिक्त संगीत सोनी ने 26 रन और शशांक चंद्राकर ने 20 रनों का योगदान दिया। विदर्भ की ओर से प्रफुल्ल हिंगे ने 3 विकेट प्राप्त किए, जबकि दर्शन नालकंडे और यश कदम ने 2-2 विकेट लेकर छत्तीसगढ़ की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार विदर्भ ने छत्तीसगढ़ को 34 रनों से हराकर मुकाबले में जीत दर्ज की।

छत्तीसगढ़ जल्द ही मखाना उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा: डॉ. चंदेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला की हुई शुरुआत



रायपुर। छत्तीसगढ़ में मखाना उत्पादन एवं प्रसंस्करण की संभावनाओं पर विचार मंथन हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड तथा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान में आज कृषि महाविद्यालय, रायपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना कार्यशाला का शुभारंभ हुआ।

स्वामी विवेकानन्द सभागार में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी तथा जिला पंचायत धमतरी के अध्यक्ष अरूण सार्वा उपस्थित थे।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि अपने अनोखे पौष्टिक गुणों की वजह से आज मखाना दुनिया भर में सुपर फूड के नाम से विख्यात हो रहा है और सेहत से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय भी हो चुका है। डॉ. चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को मखाने की खेती हेतु प्रशिक्षण और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड में शामिल होने के बाद से छत्तीसगढ़ में भी मखाना की खेती में तेजी से विस्तार हुआ है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ एक मखाना राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाएगा।

चंद्रहास चंद्राकर एवं सुरेश चंद्रवंशी ने किसानों से मखाना की खेती को अपनाने का आव्हान किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के लगभग 250-300 किसान एवं महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों सहित मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और उड़ीसा के किसान, कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर मखाना के विभिन्न उत्पादों एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर आयोजित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में मखाना के बीजों की पॉपिंग कर मखाना पॉप्स बनाने की विधि का जीवंत प्रदर्शन किसानों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। प्रदर्शनी में किसानों को मखाने की खेती के संबंध में तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।

कार्यशाला में मखाना की उन्नत खेती, प्रसंस्करण, मशीनीकरण, मूल्य संवर्धन, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा विपणन से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। विख्यात मखाना वैज्ञानिक डॉ विद्यानाथ झा सेवानिवृत्त प्राध्यापक, दरभंगा बिहार ने मखाना फसल के बारे में परिचय देते हुए किसानों को इसके इतिहास एवं सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइडेट्स, अमिनों एसिड्स, बिटामिन्स, मिनरल्स तथा एंटी आक्सीडेट्स से भरपूर होने तथा लगभग नगण्य वसा होने के वजह से मखाना सुपर फूड कहलाता है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मखाने की खेती के बारे जानकारी प्रदान की। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान के वैज्ञानिक डॉ. राहुल कुमार राउत ने मखाना प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के संबंध में जानकारी दी।

डॉ. अनिल कुमार प्रमुख अन्वेषक मखाना अनुसंधान परियोजना ने मखाना की खेती से उद्यमिता विकास विषय पर सारगर्भित जानकारी दी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फूल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. घनश्याम दास साहू एवं कीट विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉ. गजेन्द्र चन्द्राकर ने छत्तीसगढ़ में मखाने की खेती की संभावनाएं, विस्तार, कठिनाईयां तथा उनके निराकरण के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला के दौरान आयोजित वैज्ञानिक परिचर्चा में मखाना उत्पादक किसानों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण किया गया।

एनआईबीएसएम में किसानों को सरसों की वैज्ञानिक खेती का प्रायोगिक प्रशिक्षण

रायपुर । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, रायपुर में खेत बचाओ अभियानदूरबी 2026 के अंतर्गत किसान जागरूकता एवं सरसों की उन्नत खेती पर प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन, रबी फसलों के विविधीकरण तथा सरसों की उन्नत खेती की तकनीकों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को धान की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिलाना चाहिए।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवक पर चाकू से हमला आरोपी फरार

बिलासपुर। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अपोलो अस्पताल चौक के पास मंगलवार देर रात आधा दर्जन से अधिक युवकों ने करीब दो घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। वार इतना तेज था कि चाकू उसकी पीठ में ही धंस गया। घायल युवक किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा, जहां परिजनों ने उसकी पीठ में चाकू फंसा देखा। उसे गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती कराया गया है। लिंगियाडीह अपोलो चौक निवासी ईश्वर गोंड मंगलवार रात करीब 11:30 बजे बाइक से रामनगर की ओर जा रहा था। रास्ते में खड़े कुछ युवकों ने 3 साल पुरानी रंजिश के चलते उसे रोक लिया। कहासुनी के बाद आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद ईश्वर जान बचाने के लिए वहां से भागकर घर पहुंचा। परिजनों ने उसकी पीठ में चाकू फंसा देखा तो घबरा गए। वे तत्काल उसे सिम्स लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है।

रंगोली नहीं बनाई तो पड़ोसी ने युवती को पीटा

भिलाई। रंगोली बनाने से मना करने पर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पड़ोसी युवक ने 19 वर्षीय सुमन साव को पहले गालियां दीं, फिर हाथ-मुक्कों और थप्पड़ से पीट दिया। घटना 24 नवंबर की शाम बिहारी मोहल्ले के शास्त्री नगर कैंप-1 में हुई। सुमन साव के मुताबिक, वह अपनी भाभी बॉबी साव के घर के सामने, सुलभ शौचालय के पीछे गई थी। इसी दौरान भाभी के पड़ोसी नवीन साव की मां ने उससे अपने घर के सामने रंगोली बनाने को कहा। किसी कारणवश सुमन रंगोली नहीं बना पाई। तो उसने ताना मारते हुए विवाद शुरू कर दिया। इसी बीच शाम करीब 7 बजे नवीन भी वहां आ गया। उसने सुमन पर अपने माता-पिता को गाली देने का आरोप लगाते हुए मां-बहन की गालियां देनी शुरू कर दीं। सुमन ने गाली देने से मना किया तो नवीन ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में सुमन के बाएं गाल और दाएं हाथ में चोट आई है।

म्यूल बैंक खाताधारकों पर बड़ी कार्रवाई, कमीशन के लालच में बैंक खाते देने वाले आठ आरोपी गिरफ्तार

बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड एवं मोबाइल फोन जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। मुख्यालय के निर्देशानुसार साइबर अपराधों एवं म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत दुर्ग पुलिस द्वारा थाना सुपेला, थाना पुरानी भिलाई एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम के माध्यम से कार्रवाई की गई। बैंक खातों के विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में उपयोग किए गए बैंक खातों के 08 खाताधारकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।



साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी से प्राप्त रकम को विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित करने एवं उसकी पहचान छिपाने के लिए म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया जा रहा था। विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ खाताधारकों द्वारा कमीशन एवं आर्थिक लाभ के लालच में अपने बैंक खाते तथा अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जा रहे थे। जांच में यह तथ्य सामने आया कि खाताधारकों को एजेंटों के माध्यम से 5,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का कमीशन अथवा प्रतिफल देने का प्रलोभन देकर बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं मोबाइल सिम कार्ड प्राप्त किए गए थे। इन खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त अवैध धनराशि के लेन-देन एवं हस्तांतरण के लिए किया गया। संबंधित खातों में लाखों रुपये से अधिक की राशि का ट्रांजेक्शन होना पाया गया।

प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों, बैंक खातों के विश्लेषण एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 26.11.2026 को थाना सुपेला के एयू बैंक से संबंधित 03 खाताधारकों तथा थाना पुरानी भिलाई के बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित 05 खाताधारकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। दोनों थानों में पंजीबद्ध अपराधों में कुल 08 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। आरोपियों द्वारा कमीशन के लालच में अपने अथवा अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते एजेंटों के माध्यम से साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। इसके लिए बैंक खातों से संबंधित पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक एवं सिम कार्ड 5,000 से 15,000 रुपये तक के प्रतिफल पर दिए जाते थे। बाद में इन खातों का उपयोग ऑनलाइन साइबर ठगी से प्राप्त रकम को प्राप्त करने एवं अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था, जिससे ठगी की रकम के वास्तविक स्रोत एवं लाभार्थियों की पहचान छिपाई जा सके।

उक्त कार्रवाई में थाना सुपेला, थाना पुरानी भिलाई एवं एसीसीयू दुर्ग की पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों का परीक्षण एवं संबंधित खाताधारकों की पहचान कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी व्यक्ति को कमीशन अथवा आर्थिक लाभ के लालच में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल सिम अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी उपलब्ध न कराएं।

आपके बैंक खाते का उपयोग साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में होने पर आप भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। यदि आपके बैंक खाते अथवा बैंकिंग दस्तावेजों का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग किया गया है, तो तत्काल संबंधित बैंक, नजदीकी पुलिस थाना अथवा साइबर पुलिस को सूचना दें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। आपका बैंक खाता, आपकी जिम्मेदारी। बैंक खाते का दुरुपयोग रोकें और साइबर अपराधियों के विरुद्ध पुलिस का सहयोग करें।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

- जावेद खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी शांति नगर, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
- सोहेल असरफ खान, उम्र 29 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 39, अय्यप्पा नगर, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
- मंजीत कौर, निवासी आकांक्षा कुंज, शिव मंदिर, भिलाई, वर्तमान पता जी.के. मार्ट के पास, श्याम नगर, बोरसी, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग।
- गुरुद्वीप सिंह चिड्डा उर्फ राहुल, उम्र 30 वर्ष, निवासी रावतपुरा कॉलेज के पास, कुम्हारी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग।
- विकास कुमार राणा, उम्र 23 वर्ष, निवासी राजीव पारा, बिजली नगर, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
- तरुण कुमार पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी महामाया पारा, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
- मुन्नवर खान, उम्र 30 वर्ष, निवासी विश्व बैंक कॉलोनी, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
- परमीली राजेश कुमार, उम्र 33 वर्ष, निवासी ईश्वर किराना स्टोर्स, आदर्श नगर, कैम्प-01, छावनी, थाना छावनी, जिला दुर्ग।

बच्चा बेचने के लिये 15 साल की नाबालिग को बनाया बालिग

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त के मामले में एक और खुलासा हुआ है। सिंडिकेट के सदस्यों ने ओडिशा की 15 साल की नाबालिग को फर्जी आधार कार्ड के जरिए 21 साल का दिखाया। इतना ही नहीं, उसके नाम से फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र भी तैयार कराया गया। इसी दस्तावेज के आधार पर उसकी डिलीवरी कराई गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पीओसीएसओ एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं।



पुलिस जांच में सामने आया है कि, नाबालिग को मुफ्त इलाज और डिलीवरी कराने का झांसा देकर रायपुर लाया गया था। यहां उसकी मुलाकात बच्चा बेचने वाले सिंडिकेट से जुड़ी महिलाओं से कराई गई। आरोप है कि इन महिलाओं ने उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर नवजात को बेचने की साजिश रची। 4 नवंबर 2026 को गुढ़ियारी स्थित दिवाकर अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई। इसके बाद नवजात के दस्तावेज तैयार किए गए। जांच में सामने आया कि किशोरी की असली उम्र छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड और जन्म प्रमाण-पत्र का इस्तेमाल किया गया।

इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा आजाद चौक पुलिस की कार्रवाई के बाद हुआ था। पुलिस को दो महिलाओं के बीच सड़क पर विवाद की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक महिला ने बताया कि वह ओडिशा के सुंदरगढ़ की रहने वाली है। दोनों महिलाएं उसके बच्चे को बेचने और रकम के बंटवारे को लेकर विवाद कर रही थीं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ में बच्चा बेचने के नेटवर्क से जुड़ी महिलाओं के नाम सामने आए। आरोपियों ने डॉ. खिर सिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा समेत अन्य लोगों की भूमिका की जानकारी दी।

पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7वें आरोपी की पहचान जितेन्द्र खेतान (36) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, पहले गिरफ्तार कृतिका साहू ने एक नवजात बच्ची को जितेन्द्र को बेचा था।

पुलिस जांच में सामने आया है कि रायपुर से संचालित इस सिंडिकेट के जरिए छत्तीसगढ़ समेत देश के 8 राज्यों में 26 से ज्यादा नवजात बच्चों की खरीद-बिक्री की गई। इनमें बिलासपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर और चेन्नई के अलावा मध्यप्रदेश और राजस्थान के मामले भी शामिल हैं।

इस नेटवर्क में डॉक्टर, दलाल, केयरटेकर, अकाउंटेंट, नगर निगम के कर्मचारी और नि:संतान दंपतियों की जानकारी जुटाने वाले बिचौलिए शामिल बताए गए हैं।

रायगढ़ में दुकान से 20 क्विंटल अवैध धान जब्त, मंडी जांच दल की कार्रवाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। रायगढ़ जिले में धान खरीदी के बीच अवैध धान के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई की जा रही है। घरघोड़ा क्षेत्र के ग्राम कारीछापर में एक दुकान की जांच के दौरान 20 क्विंटल अवैध धान मिला। जांच टीम ने 50 बोरियों में रखे धान को जब्त कर दुकान संचालक जनक निषाद के खिलाफ मंडी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।



जानकारी के अनुसार, जिले में संदेह के आधार पर खाद्य दुकानों और गोदामों की जांच की जा रही है। इसी दौरान मंडी जांच दल ने ग्राम कारीछापर में जनक निषाद की दुकान का निरीक्षण किया। यहां जांच में 50 बोरियों में 20 क्विंटल धान भंडारित मिला। इसके बाद टीम ने धान जब्त कर कार्रवाई की। मंडी विभाग की ओर से अवैध धान के भंडारण, परिवहन और खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने के लिए नियमित जांच की जा रही है। जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

स्टील-प्लांट में गर्म डस्ट गिरने से पांच मजदूर झुलसे

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुंद। महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र स्थित करणी कृपा पावर स्टील प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। 24 नवंबर की रात औद्योगिक भट्ठी की सफाई के दौरान गर्म डस्ट 5 मजदूरों पर गिर गया। हादसे में सभी मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए रायपुर के कालड़ा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। यहां बर्न यूनिट में उनका इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक, हादसा ग्राम खैरझिटी-कौंवाझर के बीच स्थित प्लांट में हुआ। पांचों मजदूर भट्ठी की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान भट्ठी में जमा गर्म डस्ट अचानक उनके ऊपर गिर गया। डस्ट पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। इसकी चपेट में आने से सभी मजदूर झुलस गए। हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन ने एंबुलेंस से घायलों को रायपुर भेजा। डॉक्टर को रिपोर्ट का इंतजार है। घटना सकरी थाना क्षेत्र की है। घुरु निवासी मीना डहरिया ने बताया कि वह रोजी-मजदूरी कर परिवार चलाती हैं। उनकी बेटी आरुषि (17) एक घर में बच्चों की देखभाल का काम करती थी। बुधवार सुबह करीब 8 बजे आरुषि रोज की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद मीना भी अपने काम पर चली गईं।

मीना के मुताबिक, दोपहर में मोहल्ले के युवक दुर्गेश सूर्यवंशी ने आरुषि के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उसे मिलने बुलाया। परिचित होने के कारण आरुषि उससे मिलने चली गई। कुछ देर बाद आरुषि ने अपनी मां को फोन किया, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण मीना कॉल रिसीव नहीं कर सकीं। काम से छूटने के बाद जब मां ने बेटी को फोन किया, तो वह रोते हुए बताने लगी कि दुर्गेश उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है। घबराहट में आरुषि अपनी लोकेशन नहीं बता पाई। मीना को लगा कि दोनों के बीच का विवाद शांत हो जाएगा, इसलिए वह फिर काम में लग गई। मीना ने बताया कि शाम करीब 6 बजे दुर्गेश ने फोन कर जानकारी दी कि आरुषि को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन कर बताया कि आरुषि ने फांसी लगा ली है और उसे सिम्स लाया गया है। बेटी का शव देखकर मीना ने दुर्गेश पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरुषि के पैर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान हैं। दुर्गेश ने पीट-पीटकर उसकी हत्या की है और अब घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है।

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। पोस्टमॉर्टमरिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।



सुनील कालड़ा के अनुसार, मिथिलेश्वर 75 प्रतिशत, लाल सिंह 45 प्रतिशत, राजकुमार 35 प्रतिशत, भागवत 55 प्रतिशत और हेमंत 60 प्रतिशत तक झुलसे हैं। सभी की हालत गंभीर बताई गई है।

प्लांट की औद्योगिक भट्ठी में गर्म डस्ट की चपेट में आने से पिछले तीन-चार साल में कई हादसे होने की जानकारी सामने आई है। जिसमें मजदूरों की मौत भी हो चुकी है।

सुरक्षा इंतजामों की जांच जरूरी

भट्ठी की सफाई जैसे जोखिम भरे काम में डस्ट का पूरी तरह ठंडा होना और सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। यह जांच का विषय है कि हादसे के समय डस्ट का तापमान जांचा गया था या नहीं। मजदूरों को जरूरी सुरक्षा उपकरण दिए गए थे या नहीं और सफाई के दौरान तय सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं।

प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग

लगातार हादसों की जानकारी सामने आने के बाद प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की मांग उठ रही है। प्रशासन और औद्योगिक सुरक्षा विभाग को घटना की जांच कर यह पता लगाना चाहिए कि हादसा किन कारणों से हुआ। जांच में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

डकैती की कोशिश करने वाले 2 नाबालिग समेत 5 पकड़ाए

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के खमतराई इलाके में ज्वेलरी दुकान में डकैती की कोशिश करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के साथ एक नाबालिग बालक और एक बालिका को भी पकड़ा है। आरोपियों के पास से गैस सिलेंडर, कटर मशीन, दोपहिया वाहन और 4 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, घटना 17 नवंबर की रात करीब 12 बजे की है। खमतराई के श्रीनगर में स्थित सुरेश ज्वेलर्स के संचालक सुरेश धीमन 13 नवंबर को दुकान बंद कर बाहर गए थे। 18 नवंबर को लौटने पर उन्हें घटना का पता चला। दुकान के सीसीटीवी कैमरे पर कागज चिपका हुआ था और ताला गैस कटर से कटा मिला।



शिकायत मिलने के बाद खमतराई थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। दुकान संचालक और आसपास के लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की पहचान की।

पूछताछ में वारदात की कोशिश करना कबूला

जांच के दौरान पुलिस को खमतराई निवासी वासुदेव सरकार, गुंजन बार और नाज नौशाद के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने एक नाबालिग बालक और बालिका के साथ मिलकर दुकान में डकैती की कोशिश करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को भी पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल दोपहिया वाहन, गैस सिलेंडर, लोहे की कटर मशीन, हेलमेट और 4 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा अन्य सामान भी बरामद किया गया है। शुरुआत में पुलिस ने चोरी के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। जांच के दौरान डकैती के प्रयास से जुड़े साक्ष्य मिलने पर केस में बीएनएस की धारा 310(4) भी जोड़ी गई है।

बिलासपुर में 17 साल की लड़की की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 17 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मां ने मोहल्ले के युवक दुर्गेश सूर्यवंशी पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मां के मुताबिक, बुधवार दोपहर दुर्गेश ने मैसेज कर बेटी को मिलने बुलाया था।

मां का आरोप है कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है। वहीं, पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमॉर्टम कराया है। पुलिस



10 घंटे में दो नाबालिग बच्चियां बरामद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र से लापता हुई दो नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने 10 घंटे के भीतर बरामद कर लिया। दोनों बच्चियां सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरसींवा में मिलीं। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित बरामद कर जरूरी कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक, दोनों बालिकाओं के लापता होने की सूचना मिलने पर उरला थाने में अपराध क्रमांक 615/2026 और 616/2026 के मामला नाबालिगों से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने तत्काल विशेष टीम बनाकर तलाश शुरू की।

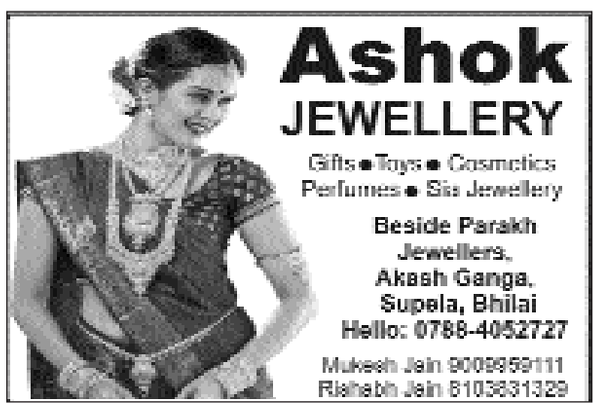


पुलिस ने बच्चियों की तलाश के लिए तकनीकी सतहत बीएनएस की धारा 137(2) में केस दर्ज किया गया था। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया। इनसे मिली जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरसींवा तक पहुंची। यहां दोनों बच्चियां सुरक्षित मिल गईं।

डीएसपी नॉर्थ जोन दीपमाला कश्यप के निर्देश पर टीम गठित की गई थी। कार्रवाई एडीसीपी आदित्य पांडेय और एसीपी उरला पूर्णिमा लामा के पर्यवेक्षण में हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक सुधांशु बघेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार तलाश की और 10 घंटे के भीतर दोनों बालिकाओं को बरामद कर लिया। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

चाकू दिखा कर लूट, पांच नाबालिग पकड़े गए

बिलासपुर। देर रात चाकू दिखाकर राहगीरों से मोबाइल और नकदी लूटने व झपटमारी की तीन वारदातों में पुलिस ने पांच नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों ने 24 नवंबर की रात लगातार तीन वारदातों को अंजाम दिया था। कुम्हारपारा निवासी अक्षय कुमार 24 नवंबर की रात 3 बजे जा रहे थे, तभी स्कूटी सवार दो नाबालिगों ने चाकू दिखाकर उनका सामान लूट लिया। इसके बाद तालापारा के बजरंग चौक स्थित नवजीवन अस्पताल के पास दूसरे युवक से मोबाइल और 900 रुपए लूटे। तीसरी वारदात 30 मिनट बाद मंगला चौक बाइपास रोड पर श्रीवास धर्मशाला के पास हुई। सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर पुलिस ने पांचों को पकड़ लिया।







संवेदनाओं से सुशासन की नई इबारत लिख रहे हैं मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री जनदर्शन शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु, जनमानस को उम्मीदों को साकार करने का मिला भरोसा

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नेतृत्व की सार्थकता इस बात में निहित है कि सामान्य जन की पीड़ा को महसूस करना, किसी बुजुर्ग की आंखों में छिपी विवशता को समझना, एक मां की चिंता को अपनी चिंता मानना और संघर्ष कर रही किसी बेटी के सपनों को टूटने से बचाने के लिए आगे आना यही मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली में मानवीय संवेदनाओं का यही सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। उनके लिए जनसेवा महज एक प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों से जुड़ा एक संकल्प है। उनकी सहजता, सरलता और आत्मीयता शासन को आम नागरिकों के और करीब ला रही है।





किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की सफलता का आकलन केवल विकास के आंकड़ों, अधोसंरचनाओं के निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन से नहीं किया जा सकता। उसकी वास्तविक कसौटी यह है कि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली में इसी विचार की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उनके नेतृत्व में विकास और मानवीय संवेदनाएं एक दूसरे की पूरक बन रही हैं। शासन की प्राथमिकताओं में जहां प्रदेश की प्रगति है, वहीं उस प्रगति के केंद्र में आम नागरिक का सुख, सम्मान और बेहतर भविष्य भी है।

मुख्यमंत्री साय के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता है। पद की गरिमा के साथ व्यवहार की सरलता बनाए रखना उनके नेतृत्व को विशिष्ट बनाता है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में जब प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से आए नागरिक उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं, तब उनके व्यवहार में एक अभिभावक जैसी आत्मीयता दिखाई देती है। किसी की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, उसकी परिस्थितियों को समझना और समाधान के लिए तत्काल पहल करना संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है।

संवेदनशीलता का अर्थ केवल किसी की पीड़ा सुन लेना नहीं, बल्कि उस पीड़ा को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करना भी है। कोरबा जिले के 83 वर्षीय परसराम राठौर के जीवन में तीन दशकों बाद स्पष्ट आवाजें सुन पाने की खुशी इसी संवेदनशीलता का उदाहरण है। मुख्यमंत्री के मुख से निकले शब्द, 'बाबा, चिंता मत कीजिए', केवल आश्वासन नहीं थे, बल्कि उनमें एक बुजुर्ग के प्रति सम्मान और आत्मीयता का भाव भी निहित था। तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराने की पहल ने उन शब्दों को सार्थकता प्रदान की। शासन की दृष्टि से यह एक छोटी-सी सहायता हो सकती है, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए यह जीवन की एक बड़ी खुशी थी। ऐसे ही क्षण जनसेवा को मानवीय गरिमा प्रदान करते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण पक्ष बच्चों के भविष्य को लेकर उनकी चिंता है। किसी परिवार के लिए इससे अधिक पीड़ादायक स्थिति क्या हो सकती है कि आर्थिक अभाव के कारण वह अपने बच्चे का उपचार तक न करा सके। ऐसे समय में शासन से मिला सहयोग केवल चिकित्सा मदद नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बन जाता है। छह वर्षीय अयांश के पैरों के उपचार और तीन वर्षीय पार्थ साहू की आंखों के बेहतर इलाज के लिए मुख्यमंत्री की पहल इसी मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। इन बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता में एक संवेदनशील अभिभावक का भाव दिखाई देता है।

मुख्यमंत्री साय का दृष्टिकोण केवल अभावों को दूर करने तक सीमित नहीं है। वे प्रदेश की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही बेटियों की उपलब्धियों की सराहना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहयोग का भरोसा देना उनकी सकारात्मक सोच को अभिव्यक्त करता है। एक संवेदनशील नेतृत्व जहां कमजोर वर्गों को संबल प्रदान करता है, वहीं प्रतिभाशाली युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने का प्रयास भी करता है। सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक दक्षता का विशेष महत्व है, लेकिन इन सभी के साथ मानवीय संवेदनाओं का समावेश ही सुशासन को पूर्णता प्रदान करता है। जब शासन नागरिकों की कठिनाइयों को समझता है, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता है और उन्हें सम्मान के साथ अपनी बात रखने का अवसर देता है, तब लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जनदर्शन शासन और जनता के बीच इसी विश्वास का सेतु बन रहा है। विकास की चमकती तस्वीरों के बीच किसी जरूरतमंद के चेहरे पर लौटी मुस्कान का अपना अलग महत्व होता है। किसी बुजुर्ग को फिर से सुनने की खुशी, किसी मां को अपने बच्चे के स्वस्थ होने की उम्मीद और किसी बेटी को अपने सपनों को साकार करने का भरोसा मिलना ऐसी उपलब्धियां हैं, जिन्हें केवल आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता। संवेदनाओं से समृद्ध नेतृत्व ही जनकल्याणकारी शासन की मजबूत आधारशिला तैयार करता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल इसी दिशा में सुशासन की एक नई इबारत लिख रही है।

जशपुर की बेटी फरहीन को पढ़ाई के लिए मिली आर्थिक सहायता

जीवन में कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जब व्यक्ति को आर्थिक सहायता के साथ भावनात्मक संबल की भी आवश्यकता होती है। पिता के निधन और परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही जशपुर की बेटी फरहीन को मुख्यमंत्री से मिला सहयोग का भरोसा इसी भावनात्मक संबल का उदाहरण है। किसी बेटी को विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपनों को जीवित रखने के लिए प्रेरित करना उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिससे न केवल उनकी वर्तमान की समस्याओं का समाधान हुआ है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी सुरक्षित रखना है। मानवीय संवेदनाओं की सार्थकता तब और बढ़ जाती है, जब उनके साथ निर्णय लेने की तत्परता जुड़ जाती है। मुख्यमंत्री साय की कार्यशैली में संवेदनशीलता और प्रशासनिक सक्रियता का यही समन्वय दिखाई देता है। जरूरतमंदों को मौके पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों के उपचार की व्यवस्था के निर्देश देना शासन को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर होगा छह वर्षीय छयांश का पूरा उपचार

मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में एक पिता अपने छह वर्षीय बेटे के बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर पहुंचे। रायपुर के आमानाका क्षेत्र के कुकुरबेड़ा निवासी अमित कोटांगले अपनी बुजुर्ग माता हिरकना बाई कोटांगले के साथ बेटे छयांश के पैरों के ऑपरेशन के लिए सहायता की गुहार लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिले। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बच्चे का ऑपरेशन अब तक नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री साय ने परिवार की व्यथा को गंभीरता से सुना और तत्काल उपचार के निर्देश दिए। श्री अमित ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके दोनों बच्चों को जन्म से ही पैरों में चलने-फिरने की समस्या है। काफी कठिनाइयों के बीच उन्होंने बड़े बेटे का ऑपरेशन करवाया, जिसके बाद वह अब स्वस्थ है। लेकिन छोटे बेटे छयांश का ऑपरेशन आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रहा। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। दोनों बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी वे अपनी बुजुर्ग माता और बहन के साथ मिलकर संभाल रहे हैं। सीमित संसाधनों में बेटे का इलाज कराना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया था। परिवार की इस कठिन परिस्थिति को समझते हुए मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालक छयांश के पैरों के ऑपरेशन और बेहतर उपचार के लिए आवश्यक सहायता की तत्काल व्यवस्था की जाए। उनके निर्देश पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

सना और सानिया की खेल उपलब्धियों की मुख्यमंत्री ने की सराहना

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन में नवा रायपुर से आई मार्शल आर्ट की खिलाड़ी बेटियों सना और सानिया ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दोनों बेटियों की खेल उपलब्धियों और पढ़ाई के साथ खेल के प्रति उनके समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया। सना और सानिया ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे मार्शल आर्ट में लगातार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों गोल्डन कप सहित खेलो इंडिया गेम्स और दमन में आयोजित बीच गेम्स में भी हिस्सा लेकर पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने अपनी खेल उपलब्धियों और भविष्य की तैयारियों के बारे में भी मुख्यमंत्री को जानकारी दी। दोनों बहनें खेल के साथ शिक्षा को भी समान महत्व दे रही हैं। सना बीकॉम और सानिया बीसीए की पढ़ाई कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी इस लगन की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि पढ़ाई और खेल दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर आगे बढ़ना उनकी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने दोनों बेटियों को अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।



डीएमएफ फंड से स्थानीय विकास और जनकल्याण को दें प्राथमिकता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में जिला खनिज न्यास की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत डीएमएफ फंड के उपयोग, विकास कार्यों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्थानीय जरूरतों के सर्वेक्षण, योजनाओं की मैपिंग और परिणाम आधारित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि डीएमएफफंड का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए



किया जाए। इसके लिए स्थानीय आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कर तीन वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसमें गांवों की जरूरतों, उपलब्ध सुविधाओं, अधोसंरचना और प्रस्तावित कार्यों का स्पष्ट विवरण हो। उन्होंने राज्य बजट की योजनाओं और डीएमएफके कार्यों की मैपिंग व तुलनात्मक समीक्षा करने को कहा, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और कार्यों का दोहराव न हो। साथ ही प्रत्येक जिले में यह आकलन करने को कहा गया कि कौन से गांव बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त हो चुके हैं और किन गांवों में विकास कार्यों की जरूरत है।

बैठक में पिछली एक्शन टेकन रिपोर्ट, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में फंड वितरण, अंतर-जिला वितरण के लिए खदानों की सूची व साझा व्यवस्था, वार्षिक ऑडिट, पीएमयू तैनाती और सोशल ऑडिट पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष के अंत में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित कर डीएमएफ कार्यों व व्यय की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, वृद्धजन व दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, पशुपालन और कृषि क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए केवल वित्तीय खर्च के बजाय जमीनी लाभ और जीवन स्तर पर प्रभाव के गुणात्मक विश्लेषण पर बल दिया।

पारदर्शिता बढ़ाने और सीजी डीएमएफ पोर्टल 2.0 के प्रचार-प्रसार के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों और सामुदायिक भवनों जैसी सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए गए। इन्हें स्कैन कर नागरिक संबंधित परिसंपत्ति और पोर्टल के जरिए विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

लोकभवन में मनाया गया संविधान दिवस

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। लोकभवन रायपुर में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर लोकभवन सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था।

राज्यपाल की उप सचिव सुश्री निधि साहू सहित सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन



किया। यह संविधान के मूल सिद्धांतों, शासन की प्रकृति और मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त परिचय देती है, जिसकी शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। संविधान की उद्दिशका इस प्रकार से है- हम, भारत के लोग, भारत को एक 1(संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य , बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 2 (राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब बस्तर को स्वावलंबी बनाने की तैयारी

बस्तर संभाग के सात जिलों के 5 लाख परिवारों को आजीविका से जोड़ने का लक्ष्य, प्रति परिवार 20 से 30 हजार रुपए मासिक आय का लक्ष्य

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नक्सलवाद से मुक्ति के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति देने जा रही है। बस्तर के स्थानीय संसाधनों, प्राकृतिक संपदा और ग्रामीणों की क्षमताओं का समुचित उपयोग कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'स्वावलंबी बस्तर अभियान' की वृहद कार्ययोजना तैयार की गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने महानदी भवन, नवा रायपुर में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों एवं प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की।

उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस्तर के प्रत्येक परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार आजीविका गतिविधियों एवं सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ने से वंचित न रहे। परिवारों की रुचि, स्थानीय संसाधनों और उपलब्ध संभावनाओं के अनुरूप आजीविका गतिविधियों का चयन किया जाए।



5 लाख परिवार होंगे लाभान्वित

स्वावलंबी बस्तर अभियान के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में निवेश की कार्ययोजना तैयार की गई है। अभियान के माध्यम से बस्तर संभाग के बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा जिले की 1,885 ग्राम पंचायतों के 3,964 गांवों में लगभग 5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के माध्यम से लक्षित परिवारों की मासिक आय 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

चार प्रमुख क्षेत्रों के 52 उत्पादों पर रहेगा विशेष जोर

अभियान के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, वनोपज एवं वृक्ष आधारित आजीविका, पशुपालन तथा गैर कृषि एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से जुड़े 23 उपक्षेत्रों के लगभग 52 प्रमुख उत्पादों को चिन्हांकित किया गया है। इनमें जैविक चावल, मिलेट्स, मसाले, फ्रूट एवं सब्जियां, इमली, महुआ, काजू, बांस, कोसा, लाख, शहद, कॉफी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ढोकरा शिल्प एवं पर्यटन सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

उत्पादन से बाजार तक विकसित की जाएगी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला

अभियान के तहत केवल आजीविका के साधन उपलब्ध कराने तक सीमित न रहते हुए कच्चे माल एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, तकनीकी प्रशिक्षण, उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला विकसित की जाएगी। इसके लिए आवश्यकतानुसार कलेक्शन सेंटर, भंडारण केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां एवं शीत श्रृंखला की व्यवस्था विकसित की जाएगी। ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) संस्था द्वारा अभियान की तैयारियों में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बस्तर के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के मायस्टोर सहित विभिन्न डिजिटल विपणन माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में पांच प्रमुख उत्पादों को सात अलग-अलग स्टोर के माध्यम से बाजार में उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई।

शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा होंगे विकसित

अभियान के अंतर्गत बस्तर संभाग में पूर्व सुरक्षा कैंपों के स्थान पर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। इन केंद्रों को सेवा सेतु पोर्टल से जोड़कर ग्रामीणों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को अपने गांव के समीप ही विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से ग्रामीण परिवारों को दुधारू गाय उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही दुग्ध संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवारों को नियमित आय का स्रोत उपलब्ध हो सके।

स्वावलंबी बस्तर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य शासन के 10 विभागों की 60 योजनाओं का समन्वय किया जाएगा। ग्रामीण परिवारों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के स्व-सहायता समूहों, सहकारी संस्थाओं, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), वन धन विकास केंद्रों एवं अन्य सामुदायिक संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। अभियान के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभियान के औपचारिक शुभारंभ से पूर्व गीदम एवं कांकेर विकासखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीणों एवं स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के साथ कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, परिवारों का सर्वेक्षण तथा परिवारवार आजीविका कार्ययोजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अभियान के लिए पृथक प्रशासनिक अधिकारी की व्यवस्था करने, प्रत्येक संबंधित विभाग से नोडल अधिकारी निर्धारित करने तथा विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने और परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होते ही जमीनी स्तर पर तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950